Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 37
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 एनजीओ के सहयोग से महाराष्ट्र में तेज़ी से ...

4 संसद बनी बंधक- संविधान का अपमान कौन ...

7 कप्तान दसुन शनाका की रिकॉर्ड तोड़ पारी,...

संक्षिप्त न्यूज

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति का अभूतपूर्व विस्तारः सिंधिया

नई दिल्लीः केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज संसद में प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों के दौरान भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में आए ऐतिहासिक परिवर्तनों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारतनेट विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक तक सस्ती और तेज़ इंटरनेट सुविधा पहुँचाना है।

सिंधिया ने जानकारी दी कि ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की प्रमुख योजना भारतनेट के अंतर्गत देश की 2.56 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। भारतनेट चरण ढ और छ के तहत लगभग 42,000 करोड़ के निवेश से 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है।

मोबाइल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड में अभूतपूर्व विस्तार

केंद्रीय मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2014 में देश में 93 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 120 करोड़ हो चुके हैं। मोबाइल पेनिट्रेशन 75 प्रतिशत से बढ़कर 92 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी क्रांतिकारी बदलाव आया है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर अब 100 करोड़ से अधिक हो गई है और पेनिट्रेशन 20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 71.8 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है।

इसी प्रकार, ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि औसत ब्रॉडबैंड गति लगभग 66 एमबीपीएस तक पहुँच चुकी है। सिंधिया ने इसे डिजिटल क्रांति बताते हुए कहा कि कनेक्टिविटी अब केवल शहरी विशेषाधिकार नहीं रही, बल्कि ग्रामीण भारत तक पहुँचने वाला नागरिक अधिकार बन चुकी है।

बहुत हो चुका, अब दुनिया देखेगी पीएम मोदी की कूटनीति

40 से 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगले हफ्ते आ रहे हैं दिल्ली

नई दिल्ली। भारत की कूटनीतिक सक्रियता एक बार फिर तेज गति से आगे बढ़ती दिख रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने में जुटा है और उभरती तकनीक, व्यापार, सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दे रहा है। हम आपको बता दें कि इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण नई दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट होगा, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति 19 और 20 फरवरी को भाग लेंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार 21 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुला के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी जिसमें व्यापार, ऊर्जा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, रक्षा सहयोग और नई तकनीक जैसे कई विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी ब्राजील के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन भी होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उनसे मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को नया बल मिलेगा और ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर साझा पहल आगे बढ़ेगी।

इसके अलावा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी 17 से 19 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। दोनों

देश वर्ष 2047 तक के रोडमैप के तहत सहयोग को गहरा करने पर काम कर रहे हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी पर विशेष ध्यान रहेगा। मुंबई में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का संयुक्त शुभारंभ भी दोनों नेता करेंगे, जो साल भर मनाया जाएगा। 19 फरवरी को राष्ट्रपति मैक्रों भी एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि इस समिट में दुनिया के 40 से 50 देशों के नेता, नीति निर्माता और तकनीक विशेषज्ञ भाग ले सकते हैं। इससे भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नीति निर्माण और नैतिक उपयोग पर वैश्विक संवाद का केंद्र बनने का अवसर मिलेगा।

इन कूटनीतिक गतिविधियों के बीच रक्षा क्षेत्र से भी एक अहम खबर आई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सौदा सरकार से सरकार के बीच समझौते के जरिये आगे बढ़ेगा। योजना है कि 114 में से 90 विमान भारत में ही बनाए जाएं और इनमें करीब आधा हिस्सा स्वदेशी सामग्री का हो। भारत को इन विमानों में अपने हथियार और प्रणालियां जोड़ने का अधिकार भी होगा। वायु सेना पहले से 36 राफेल का उपयोग कर रही है, जबकि नौसेना आने वाले वर्षों में 26 राफेल एम शामिल करेगी। नए विमानों से वायु सेना की दस्ता शक्ति में कमी की समस्या कुछ हद तक दूर होगी, क्योंकि स्वीकृत संख्या 42 के मुकाबले अभी स्कवॉड्रन संख्या काफी कम है। दूसरी ओर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक वार्ता में कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर उन्होंने कहा कि हाल के संशोधन दोनों पक्षों की साझा समझ को ही दिखाते हैं और अब इस ढांचे को लागू करने तथा समझौते को अंतिम रूप देने पर काम होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में लाल किला के पास हुए विस्फोट में जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका के उल्लेख पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में भारत की चिंताओं और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को स्थान दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक कथित वीडियो टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई वीडियो है तो उसकी सच्चाई देख कर उचित कदम उठाया जाएगा। चीन के साथ बातचीत पर उन्होंने बताया कि ब्रिक्स बैठक के दौरान दोनों पक्षों में सीमा पर शांति और स्थिरता सहित कई विषयों पर चर्चा हुई और चीन ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी को समझने और सम्मान देने की बात कही।

किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- वह मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मीडियाकर्मियों पर की गई बदतमीजी की आलोचना करते हुए कहा राहुल गांधी मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते। राष्ट्रीय राजधानी में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि मीडिया को सवाल पूछने से नहीं रोका जाना चाहिए, और कहा कि विपक्ष में रहते हुए उनकी पार्टी ने कभी भी मीडिया को सवाल पूछने से नहीं रोका।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह गलत है। अगर वह मीडिया को टोकेंगे और डांटेंगे, तो सवाल कौन पूछेगा? क्या हमने कभी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है? विपक्ष में रहते हुए हमने कभी भी कांग्रेस का नाम लेकर मीडिया से कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह सब इसलिए कहा होगा क्योंकि वह मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते। उन्होंने कांग्रेस सांसदों के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने सांसदों से विपक्ष के नेता को सदन के नियमों के अनुसार बोलने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि मैंने कई कांग्रेस सांसदों से राहुल गांधी को यह समझाने के लिए कहा है कि अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ नोटिस जारी किया जा सकता है।

यह घटना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा आज सुबह भाजपा के निर्देशों का अंधाधुंध पालन करने के लिए मीडिया की आलोचना करने और इसे 'देश के लिए हानिकारक' बताने के बाद हुई है। रिजिजू ने अपने फेसबुक हैंडल पर साझा किए गए उस वीडियो पर भी बात की, जिसमें कांग्रेस सांसदों ने कथित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का उनके कक्ष में अपमान किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल वहां मौजूद थे, जबकि अन्य सांसदों ने कथित तौर पर अध्यक्ष के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया।

डीके शिवकुमार के दिल्ली दौरे से कर्नाटक तक सियासी हलचल, डिप्टी सीएम बोले- समय देगा हर सवाल का जवाब

बंगलूरू।कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। सोनिया गांधी के आवास दस जनपथ से बाहर आने के बाद शिवकुमार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वह यहां सिर्फ दिल्ली की हवा में सांस लेने नहीं आए हैं, बल्कि राजनीति करने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला समय ही हर बात का जवाब देगा।

क्या बोले डीके शिवकुमार?

जब उनसे पूछा गया कि वह प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से किससे मिले, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। शिवकुमार ने कहा कि वह सड़क पर खड़े होकर राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से उन सभी मुद्दों पर चर्चा कर ली है, जो जरूरी थे। शिवकुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि दिल्ली आने पर उन्हें सभी मामलों की जानकारी देनी होती है और उन्होंने हर विषय पर विस्तार से बात की है।

असम विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा

शिवकुमार ने आगे कहा, हमने असम विधानसभा चुनाव और अन्य राजनीतिक मामलों पर चर्चा की है। उन्होंने वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और अन्य नेताओं के साथ मिलकर असम में कांग्रेस की सरकार लाने की तैयारी पर चर्चा की। शिवकुमार के बयानों से कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल मचने की संभावना है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद शिवकुमार आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं।

डीके सुरेश ने दिया बड़ा बयान

शिवकुमार के समर्थक विधायक चाहते हैं कि पार्टी का आलाकमान दखल दे और नेतृत्व को लेकर चल रही उलझन को खत्म करे। इसी बीच उनके भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में बाहर से आए लोगों को ज्यादा महत्व मिल रहा है। इसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर सीधा निशाना माना जा रहा है। सिद्धारमैया पहले दूसरी पार्टी में थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए थे।

तमिलनाडु में निवेश की बहार,सीएम एमके स्टालिन का दावा- 11.19प्रतिशत ग्रोथ से युवाओं को मिलेगा रोजगार

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कन्वर्जन कॉन्क्लेव 2026 के दौरान निवेशकों से राज्य में निवेश जारी रखने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार निवेश का उपयोग रोजगार के अवसर पैदा करने, युवा विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए करेगी। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु ने 11.19 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही, देश की औद्योगिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत है, जबकि राज्य की वृद्धि दर इससे तिगुनी है।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि द्रविड़ मॉडल विकास का एक ऐसा मॉडल है जो परिणाम देता है और जनता के कल्याण के लिए है। आज का यह सम्मेलन इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए है। तमिलनाडु के विकास के बारे में सुनकर कुछ लोग शायद विश्वास न कर पाएं या इसे पचा न पाएं। आज का यह सम्मेलन उनके सवालों का जवाब है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार न केवल निवेश की बात करती है, बल्कि राज्य के भीतर संबंध भी बनाती है।

स्टालिन ने कहा कि आज जारी किए गए आंकड़े एक रिकॉर्ड हैं जिसे कोई और नहीं तोड़ सकता। मैं आज यहां आए सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे इस सम्मेलन को जनता तक पहुंचाएं। आमतौर पर, सभी राज्य सरकारें निवेश सम्मेलन आयोजित करती हैं और अपने राज्य में लाए गए निवेशों के बारे में बात करती हैं, लेकिन हम संबंध बनाते हैं और यह उदाहरण पेश करते हैं कि एक राज्य को कैसे काम करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही नहीं रुकती, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि उनका कार्यान्वयन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं सृजित अवसरों की संख्या, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, पर नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कंपनियां सोचती हैं कि तमिलनाडु निवेशकों को यह भरोसा दिलाता है कि उनके समझौता ज्ञापन ज़मीनी स्तर पर लागू होने चाहिए। हम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही नहीं रुकते, बल्कि उसका पालन सुनिश्चित करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे युवाओं को नौकरी का प्रस्ताव पत्र मिले। सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि तमिलनाडु निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान है।

ट्रेड डील से कश्मीरी सेब बागानों पर मंडराया खतरा!

उमर अब्दुल्ला बोले - अमेरिकी सेब आने से घटेगी कश्मीरी सेबों की माँग

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यदि सेब, अखरोट और बादाम जैसे उत्पादों का आयात बिना शुल्क या बहुत कम शुल्क पर होने लगा, तो इसका सीधा नुकसान जम्मू-कश्मीर के किसानों को होगा।

भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर जम्मू-कश्मीर के बागवानी क्षेत्र में गहन बहस छिड़ गई है। एक ओर कई फल उत्पादक और व्यापारी इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ किसान और कारोबारी इसे प्रतिस्पर्धा बढ़ने, गुणवत्ता सुधार और कीमतों में स्थिरता का अवसर भी बता रहे हैं। इस समझौते का प्रभाव विशेष रूप से सेब, अखरोट और बादाम जैसे उत्पादों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिन पर जम्मू-कश्मीर की बड़ी आबादी की आजीविका निर्भर है।

बागवानी विभाग के अनुमान के अनुसार जम्मू-कश्मीर में लगभग 20 लाख लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बागवानी क्षेत्र से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। ऐसे में आयात नीति में किसी भी प्रकार का बदलाव केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों की आय, रोजगार और सामाजिक संरचना पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के अखरोट उत्पादक और व्यापारी जावेद अहमद लोन का दृष्टिकोण इससे कुछ अलग है। उनका मानना है कि बाहरी उत्पादों के आने से स्थानीय किसानों को अपनी गुणवत्ता सुधारने की प्रेरणा मिलेगी। उनके अनुसार संरक्षण की नीति लंबे समय तक किसानों को सुस्त बना देती है, क्योंकि उन्हें एक तय बाजार मिल जाता है। लोन का कहना है कि कश्मीर में बादाम और अखरोट की कीमतें अक्सर बिना स्पष्ट कारण के ऊपर-नीचे होती रहती हैं।

मनी म्यूल यानी वह व्यक्ति जो अवैध रूप से प्राप्त पैसों को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कहीं ट्रांसफर करता है या भेजता है।

मनी म्यूल न बनें!

आपका बैंक खाता = आपकी पूंजी

- पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बैंक खाता इस्तेमाल न करने दें।
- अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके बैंक खाते के ज़रिए पैसा प्राप्त करता है या भेजता है तो आपको जेल हो सकती है।
- अपने बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड किसी को न बताएं।

आपके खाते की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा।

अवैध कमाई के जाल में न फंसें।

अधिक जानकारी के लिए देखें https://rbikehtahai.rbi.org.in
अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए rbikehtahai@rbi.org.in पर भेजें।
आधिकारिक व्हॉट्सऐप नं. 99990 41935 / 99309 91935
क्यूआर कोड स्कैन करें।

जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

'शिवसेना यूबीटी पार्षदों ने चंद्रपुर में BJP का समर्थन करने के लिए 1 करोड़ लिए', मनसे नेता का दावा

दिव्यांश

महाराष्ट्र के चंद्रपुर नगर निगम के मेयर चुनाव को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस / मनसे) के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने आरोप लगाया है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के पार्षदों को भाजपा का समर्थन करने के लिए एक-एक करोड़ रुपये दिए गए। हालांकि शिवसेना यूबीटी और भाजपा, दोनों ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

चंद्रपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और माना जा रहा था कि मेयर पद उसी को मिलेगा।

लेकिन चुनाव में अचानक समीकरण बदल गए और भाजपा ने शिवसेना यूबीटी के कुछ पार्षदों के समर्थन

से मेयर पद जीत लिया।

भाजपा की संगीता खांडेकर सिर्फ एक वोट से कांग्रेस उम्मीदवार वैशाली महादुले को हराकर मेयर बनीं।

वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रशांत दनाव डिप्टी मेयर चुने गए।

मनसे नेता का क्या है आरोप?

संदीप देशपांडे ने दावा किया कि हर शिवसेना यूबीटी पार्षद को ?1 करोड़ दिए गए। एक निर्दलीय पार्षद को ?50 लाख मिले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब शिवसेना यूबीटी भाजपा का समर्थन करे तो ठीक, लेकिन मनसे करे तो गलत बताया जाता है।

आरोपों पर शिवसेना यूबीटी और भाजपा की प्रतिक्रिया

पार्टी के चंद्रपुर जिला अध्यक्ष संदीप गिरहे ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा अगर संदीप देशपांडे सबूत दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी कहा कि हार के लिए कांग्रेस की स्थानीय गुटबाजी जिम्मेदार है, न कि कोई सौदेबाजी। भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि संदीप देशपांडे के आरोपों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये सिर्फ मनसे और शिवसेना यूबीटी के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है।

विपक्षी गठबंधन पर असर

यह घटना विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी साथ हैं। इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष की एकता पर सवाल उठने लगे हैं।

उद्धव ठाकरे का भाजपा पर निशानाः

निकाय चुनाव में हार के बाद बोले- वफादारी की दीवार को नहीं तोड़ सकता पैसा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र में हाल ही में हुए सभी चुनावों में शिवसेना (यूबीटी) को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उद्धव ठाकरे ने भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम के चुनावों में खुब पैसा बहाया गया इसके बाद भी ये वफादारी की दीवार नहीं तोड़ पाए। 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनावों में अधिकतर पर महायुति का दबदबा रहा। इसमें से कुछ सीटों पर चुने गए शिवसेना के सदस्यों और कार्यकर्ताओं से से हिम्मत न हारने और आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार रहने को कहा।

नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम में लगातार जीत के बाद, भाजपा ने जीत की 'हैट्रिक' हासिल की है, जिससे वह राज्य में नंबर वन पार्टी बन गई है। इसके उलट, महा विकास अघाड़ी को इस चुनाव में बड़ी हार का

सामना करना पड़ा। हार मानते हुए, ठाकरे ने पार्टी सदस्यों और जीतने वाले उम्मीदवारों को हौसला बढ़ाने वाला मैसेज दिया। उन्होंने कहा आपने सच में चमत्कार किया है। आपने बहुत मुश्किल हालात में भी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने आगे कहा भले ही आज हालात ठीक न हों, भविष्य हमारा है। जिस हिम्मत से आपने ये चुनाव लड़े, वही हमारी असली ताकत है।

महायुति ने ग्रामीण महाराष्ट्र में काफी बढ़त हासिल की है। जो राज्य की रीढ़ है। ठाकरे का बयान इस बात की ओर इशारा है कि वह नई ऊर्जा के साथ वापस मैदान में लौट रहे हैं। ठाकरे 2026 के ग्रामीण चुनावों की भी तैयारी में नजर आ रहे हैं। इन चुनावों को अगले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लातूर, सांगली और छत्रपति संभाजीनगर जैसे जिलों में भाजपा के प्रदर्शन ने उसकी जमीनी पकड़ को मजबूत किया है। दूसरी तरफ, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कोस्टल बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, और एनसीपी (अजीत पवार) ने पश्चिमी महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बनाए रखी।

भुसावल मंडल में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भुसावल मंडल द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस उत्साह एवं गरिमा के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर आयोजित प्रेरणादायक कार्यक्रम में रेलवे कर्मचारी, यूनियन प्रतिनिधि एवं माननीय अतिथि एकत्रित हुए और दिव्यांगजनों के सम्मान तथा सशक्तिकरण का संदेश दिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुनीत अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक तथा सुनील कुमार सुमन, अपर मंडल रेल प्रबंधक (प्रशासन) उपस्थित रहे। एम. के. मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक (तकनीकी), वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी एवं एसबीएफ कमेटी के अध्यक्ष श्री दिलीप खरात सहित अन्य वरिष्ठ शाखा अधिकारी भी मौजूद थे। विशेष अतिथि के रूप में डी. जी. जाधव, बीडीओ/भुसावल ने उपस्थित समस्त कर्मचारियों को प्रेरणादायक संबोधन दिया।

इस कार्यक्रम में 200 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें सभी यूनियनों एवं एसोसिएशनों के स्टाफ साइड सदस्य भी शामिल थे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी का मन मोह लिया।

यह आयोजन भुसावल मंडल की समावेशी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने तथा दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित करता है।

हार्बर लाइन की एसी लोकल को शानदार प्रतिक्रिया, 6.40 लाख यात्रियों ने किया सफर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

हार्बर लाइन पर हाल ही में शुरू की गई एसी लोकल सेवाओं को यात्रियों से भारी प्रतिसाद मिला । 26 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक, केवल 16 दिनों में एसी लोकल ट्रेनों से कुल 6.40 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो प्रतिदिन औसतन 40,017 यात्रियों का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज करता है।

इस अवधि के दौरान, मध्य रेल ने एसी लोकल टिकटों की बिक्री से कुल 2.38 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जो प्रतिदिन औसतन 14.90 लाख रुपये है। इसमें 1.79 करोड़ रुपये सीजन टिकटों से तथा 59 लाख रुपये यात्रा टिकटों से प्राप्त हुए हैं।

यह जबरदस्त प्रतिक्रिया दर्शाती है कि यात्री पारंपरिक नॉन-एसी प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की यात्रा से उन्नत आराम और सुविधाओं से युक्त एसी लोकल सेवाओं की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं।

वर्तमान में मध्य रेल कुल 94 एसी लोकल सेवाएं संचालित कर रहा है, जिनमें से 14 सेवाएं 26 जनवरी 2026 को हार्बर लाइन पर शुरू की गई थीं।

टिकट जाँच अभियान तेज किए गए

मध्य रेल का मुंबई मंडल अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने और वास्तविक यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एसी लोकल ट्रेनों और स्टेशनों पर नियमित रूप से विशेष टिकट जाँच अभियान चलाता है। इन विशेष जाँचों से बिना उचित टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों का पता लगाने और उन पर जुर्माना लगाने में मदद मिलती है और यह बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है।

हार्बर लाइन एसी लोकल ट्रेनों में टिकट जाँच अभियानः

26 जनवरी से 10 फरवरी 2026 की अवधि के दौरान, मुंबई मंडल की टिकट जाँच टीमों ने हार्बर लाइन एसी लोकल ट्रेनों में अनियमित यात्रा के 810 मामलों का पता लगाया और जुर्माना लगाकर

25 लाख रुपये वसूल किए।

एसी लोकल ट्रेनों में टिकट जाँच अभियानः (मेन लाइन और हार्बर लाइन संयुक्त):

वित्तीय वर्ष 2025-26 (10 फरवरी 2026 तक) के दौरान, टिकट जांच दलों ने एसी लोकल ट्रेनों (मेन लाइन और हार्बर लाइन दोनों) में बिना टिकट या बिना उचित टिकट के यात्रा करने के 1.01 लाख मामले पकड़े और 3.22 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया।

यह स्पष्ट संदेश देता है कि एसी लोकल में अनियमित यात्रा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मध्य रेल अपने यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और कुशल यात्रा प्रदान करने के प्रयासों में अग्रणी बना हुआ है, और एसी लोकल ट्रेनों का संचालन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मध्य रेल अनियमित यात्रा को रोकने और सभी यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यात्रियों से अनुरोध है कि असुविधा से बचने के लिए उचित और वैध रेलवे टिकट खरीदकर गरिमापूर्ण यात्रा करें।

'अजित दादा के अधूरे सपनों को पूरा करना हमारा दायित्व', सुप्रिया बोलीं- परिवार के लिए कठिन समय

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

एनसीपी (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने गुरुवार को कहा कि 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में निधन हुए अजित पवार के अधूरे सपनों को पूरा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है और सभी सदस्य एक-दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में सुप्रिया सुले ने कहा कि 'दादा (अजित पवार) अब हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए मैं पुराने मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। हमारे बीच जो भी चर्चाएं हुई थीं, वे हमारे बीच ही रहेंगी। अब हमारा कर्तव्य है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करें।'

NCP विलय की चर्चा पर क्या बोलीं

एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि परिवार अभी शोक में है, इसलिए इस समय ऐसे विषयों पर चर्चा करना ठीक नहीं है।

विमान हादसे पर जांच की मांग

वहीं एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार की तरफ से उठाई गई शंकाओं

पर सुले ने कहा कि उनकी चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की विस्तृत जांच का भरोसा दिया है। सुप्रिया सुले ने कहा कि 'कई सवाल हैं- क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इसे रोका जा सकता था, इन सबका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए।'

अजित पवार की योजनाओं का जिक्र

सुप्रिया सुले ने बताया कि अजित पवार के कार्यकाल में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि और कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर हुई थी। उन्होंने पुणे की सफल 'कृषक' पहल का भी जिक्र करते हुए कहा कि यह अजित पवार का सपना था और इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

नेताओं का जताया आभार, बेटी की शादी पर बयान

सुप्रिया सुले ने यह भी बताया कि जब शरद पवार अस्पताल में भर्ती थे, तब विभिन्न दलों के नेताओं ने फोन कर हालचाल पूछा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित सभी नेताओं का धन्यवाद किया। अपनी बेटी रेवती की सरंग लखानी से शादी की घोषणा पर सुले ने कहा कि दोनों एक साल से एक-दूसरे को जानते हैं और इस रिश्ते पर कई महीनों से बातचीत चल रही थी। उन्होंने बताया कि शादी का फैसला अजित पवार के जीवित रहते ही हो गया था और उनके आशीर्वाद से यह रिश्ता तय हुआ।

किसानों और व्यापार समझौते पर सवाल

किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर किसानों को फायदा हो तो सभी खुश होंगे, लेकिन किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते से भारत को क्या लाभ होगा, यह सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए। उन्होंने केंद्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर दिए जा रहे जोर का भी उल्लेख किया।

अजित पवार के विमान हादसे पर सवाल

संजय राउत का केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोप

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार के 'षड्यंत्र' और 'तोड़फोड़' के आरोपों का भी समर्थन किया।

पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरते हुए कहा, इस राज्य और देश की जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी हैं। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो या राज्य पुलिस, जनता का इन पर से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र सरकार के समय में बड़े मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं होती। सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए जांच में पक्षपा करती है।

उन्होंने कहा कि जो विमान हादसे का शिकार हुआ था वह गुजरात से आया था, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। जिस विमान में अजित दादा सवार थे, वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसे को देखिए, लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि वह विमान कैसे गिरा? राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी अपील की कि वे रोहित पवार के आरोपों को गंभीरता से लें और उन्हें राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज न करें। रोहित पवार तथ्यों के साथ विस्तृत जानकारी रख रहे हैं। अगर अजित दादा के निधन पर शोक सच्चा है, तो शिंदे को रोहित पवार और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलानी चाहिए। एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे सच से बचने का तरीका है।

पश्चिम रेलवे

एयर कंडीशनिंग हेतु परामर्श सेवाएँ

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता / पी / बीसीटी द्वारा Tender Notice No. EL-4-2-379-WA-36 (R-5), dt.: 10.02.2026 (दो पैकेट प्रणाली) के अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। **कार्य एवं स्थानः** चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय कार्यालय के जीएलओ, एनेक्स भवन तथा चर्चगेट स्टेशन भवन के लिए एयर कंडीशनिंग हेतु परामर्श सेवाएँ। **कार्य की अनुमानित लागतः** 19,47,000.00 **ईएमडीः** 38,900.00 **बोली जमा करने की तिथि एवं समयः** 09.03.2026 को 15.00 बजे तक, बोली खोलने की तिथि एवं समयः 09.03.2026 को 15.30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। 1108

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

मध्य रेल

खुली निविदा सूचना

खुली ई-निविदा संख्याः केवायएन-एलडी-585-डब्लु-756-कांट-आर 1

कार्य का विवरण : मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के कल्याण और लोनावला जिलों में पुल के खंभों पर लगे ओएचई ट्रैक्शन ब्रिज के मास्ट को एपॉक्सी ग्राउटिंग और रॉक एंकरिंग द्वारा प्रतिस्थापित करना। **अनुमानित लागतः** ₹2,50,64,447.36, **ईएमडीः** ₹2,75,300/-, **निविदा पपत्र का शुल्कः** 0.00, **समापन अवधीः**12 महिने। ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथी एवं अवधि **दि. 05.03.2026 को 11:00 बजे** है। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की अधिकारीक वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा की जानकारी वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क.वि.) मध्य रेल, कल्याण के सुचना पट पर उपलब्ध है।

सुरक्षित यात्रा करें, फुटबोर्ड पर यात्रा न करें 894

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार द्वारा नंदुरबार-उधना खंड का संरक्षा निरीक्षण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार द्वारा आज नंदुरबार-उधना खंड का व्यापक संरक्षा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण का उद्देश्य इस रेलखंड पर परिचालन दक्षता, आधारभूत संरचना की विश्वसनीयता तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना था। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों के प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष, मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज सिंह सहित मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

निरीक्षण के दौरान कुमार ने मंडल अधिकारियों को संरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, समयबद्ध निवारक रखरखाव करने तथा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए, ताकि परिचालन सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी

अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निरीक्षण की शुरुआत नंदुरबार स्टेशन से हुई। महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने स्टेशन पर प्रदत्त सुविधाओं, क्रू लॉबी, रिले रुम, रनिंग रूम, स्वास्थ्य इकाई, रेलवे कॉलोनी, ART/ARME आदि का विस्तृत निरीक्षण किया।

इस अवसर पर उन्होंने नंदुरबार स्टेशन पर कैरिज एवं वैगन कमांड सेंटर का उद्घाटन भी किया। यह कमांड सेंटर रोलिंग-इन/रोलिंग-आउट परीक्षण, हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर तथा एन-रूट वाटरिंग सिस्टम की रियल-टाइम निगरानी में सहायक होगा, जिससे संरक्षा पर्यवेक्षण एवं निवारक कार्रवाई को और सुदृढ़ किया जा सकेगा।

महाप्रबंधक कुमार ने नंदुरबार एवं व्यारा स्टेशन पर मीडिया प्रतिनिधियों से भी संवाद किया तथा स्टेशनों पर किए गए निरीक्षण के निष्कर्षों की जानकारी दी। उन्होंने नंदुरबार स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों एवं व्यारा स्टेशन पर व्यारा के विधायक मोहन कोंकणी जी और मांडवी के विधायक कुंवरजी हड़पतीजी से भी भेंट की और आश्वस्त किया कि उनकी उचित मांगों एवं सुझावों पर नियमानुसार विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कुमार ने नंदुरबार-खांडबारा खंड के बीच स्पीड ट्रायल का अवलोकन किया। उन्होंने खांडबारा-खातगांव खंड में स्थित पुल संख्या 151 तथा व्यारा-लोटरवा खंड में स्थित पुल संख्या 49 का निरीक्षण किया। इसके साथ ही संबंधित खंड में वक्रों (कर्व) एवं अनुरक्षण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की। व्यारा एवं मढ़ी स्टेशनों पर उन्होंने संरक्षा समीक्षा की, जिसमें टीआरडी डिपो, टीएसएस, प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग्स तथा इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट्स का निरीक्षण शामिल था।

इस निरीक्षण के दौरान ट्रैक अनुरक्षण मानकों, पुलों की सुरक्षा, सिग्नलिंग प्रणाली, विद्युत प्रतिष्ठानों, क्रू सुविधाओं एवं यात्री सुविधाओं पर विशेष बल दिया गया।

महाप्रबंधक प्रदीप कुमार ने सुरक्षित एवं सुचारु रेल संचालन सुनिश्चित करने में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने पश्चिम रेलवे की सुरक्षा अवसंरचना को और सुदृढ़ करने तथा यात्रियों एवं माल ग्राहकों को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

पश्चिम रेलवे

अंतिम लोकेशन सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

उप मुख्य अभियंता (सिविल) वर्क्स/पी-वे, पश्चिम रेलवे, प्रथम तल, स्टेशन भवन, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 द्वारा Tender No.: CAO-C-Works-FLS-DPR-4, Date: 10.02.2026 के अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। **कार्य का नामः** पश्चिम रेलवे पर नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद-आलीराजपुर-नंदुरबार के बीच नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए अंतिम लोकेशन सर्वेक्षण (FLS) कराना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करना। **निविदा लागतः** 6,72,17,820/- **बोली सुरक्षाः** 4,86,100/- **बोली प्रारंभ तिथिः** 16/02/2026 **बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः** 02/03/2026 **निविदा दस्तावेज खोलने की तिथिः** 05/03/2026 अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं। 1113

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

जा.क्र. SRA/CO/OW/६७२५/सन २०२६ दिनांक : १२/२/२०२६

-: ऑनलाईन सोडत पध्दतीने सदनिका वाटपाची सुचना :-

कांती नगर एस. आर. ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., एफ. पी. नं. १५, टीपीएस-III, माहिम डिव्हीजन, सिटी लाईट सिनेमा समोर, माहिम, मुंबई- ४०००१६ या पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचे वाटप करणेसाठी अभियांत्रिकी विभागाकडील मंजूरीनुसार सदर इमारतीतील उपलब्ध ५१ निवासी सदनिका मा. उपमुख्य अभियंता-I, परिशिष्ट-२ सुविधा कक्ष, अभियांत्रिकी विभाग, झो.पु.प्रा., बृहन्मुंबई यांचेकडून प्राप्त परि-२/पुरवणी परि-२ प्रमाणे ५१ पात्र झोपडीधारकांना सोडतीद्वारे वाटप करण्यात येणार आहे.

परिपत्रकीय सुचनांनुसार पात्र झोपडीधारकांना सदनिकांचे ऑनलाईन सोडतीद्वारे वाटप करणेकामी मा. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर), झो.पु.प्रा., बृहन्मुंबई यांनी दि. ०१/०१/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये माझी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

अभियांत्रिकी विभागाकडून प्राप्त मंजूरीनुसार दिनांक ०१/०१/२०२६ रोजीच्या नोटीसीअन्वये ५१ पात्र झोपडीधारकांची यादी प्रसिध्द करुन दि. ०७/०१/२०२६ पर्यत आक्षेप/हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या. त्यामध्ये ०२ पात्र झोपडीधारकांनी त्यांची नावे सोडतीमधील यादीमध्ये नसल्याची हरकत घेतली होती. याबाबत मा. कार्यकारी अभियंता-जी/एन विभाग यांचेकडून दि.२०/०१/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये हरकती पडताळणी करुन त्या ०२ पात्र झोपडीधारकांची नावे समाविष्ट करण्याबाबत कळविलेले आहे. त्यानुसार ५३ पात्र झोपडीधारकांना संस्थेच्या पुनर्वसन योजनेच्या पुनर्वसन इमारतीमधील ५३ निवासी सदनिकांचे सोडत पध्दतीने वितरण बुधवार, दिनांक २८.०१.२०२६ रोजी दुपारी ०१.०० वाजता, आयोजित करण्यात आले होते. सदर दिवशी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांचे दुःखद निधन झाल्याने महाराष्ट्र शासनाने सदर दिवशी शासकीय सुट्टी जाहिर केल्याने दि. २८/०१/२०२६ रोजी आयोजित केलेली ५३ निवासी सदनिकांची सोडत या कार्यालयाकडील दि. २८/०१/२०२६ रोजीच्या नोटीसीअन्वये पुढे ढकलण्यात आली होती.

तद्नंतर मा. कार्यकारी अभियंता-जी/एन विभाग यांचेकडून दि. ०६/०२/२०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सदनिका लॉटरी प्रकीयेमध्ये आणखी ०४ पात्र झोपडीधारकांची नावे समाविष्ट करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.

त्यानुसार ५७ पात्र झोपडीधारकांना संस्थेच्या पुनर्वसन योजनेच्या पुनर्वसन इमारतीमधील ५७ निवासी सदनिकांचे सोडत पध्दतीने वितरण **सोमवार, दिनांक १६.०२.२०२६ रोजी दुपारी ०१.०० वाजता, स्थळ : प्राधिकरणाच्या कार्यालयात ऑनलाईन पध्दतीने झूम ॲप (Zoom App)वर संगणीकृत प्रणालीव्दारे आयोजित केलेली आहे.**

-: सभेचा विषय :-

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे परिपत्रक क. १६२/दि. २३.१०.२०१५ नुसार ऑनलाईन झूम ॲप (Zoom App) वर सोडत पध्दतीने पुनर्वसन योजनेच्या इमारतीमधील एकुण ५७ निवासी सदनिकांचे वाटप करणे.

Meeting ID : ८५७ ५८६६ २७२६
Passcode : १२३४५६
ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १२.०२.२०२६

शिक्का

सही/-
(विरधवल जाधव)
प्राधिकृत अधिकारी तथा सहकारी अधिकारी, (श्रेणी-२), झो.पु.प्रा., बृहन्मुंबई

एनजीओ के सहयोग से महाराष्ट्र में तेज़ी से होगा परिवर्तन- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

टाटा ट्रस्ट और नाम फाउंडेशन के साथ हुए समझौते से महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में होगा विकास

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र देश की प्रगति में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार विभिन्न एनजीओ के सहयोग से विकास की गति को बनाए रखते हुए महाराष्ट्र में तेज़ परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा कि सह्याद्री गेस्ट हाउस में टाटा ट्रस्ट और नाम फाउंडेशन के साथ हुए समझौतों से पूरे महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री संजय राठौड़, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए स्वास्थ्य, पोषण, जल सुरक्षा और आजीविका को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। इन साझेदारियों से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक पहुंचेंगी और योजनाएं जनआंदोलन का रूप लेंगी। टाटा ट्रस्ट के सहयोग से विभिन्न विभागों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की आय में वृद्धि और जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। गंभीर बीमारियों के महंगे उपचार के कारण आम नागरिकों को सीमाएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन राज्य में ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि कोई भी व्यक्ति उपचार के अभाव में मृत्यु का शिकार न हो। मुख्यमंत्री सहायता निधि में टाटा का महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे जरूरतमंद मरीजों

को सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से सरकार टाटा ट्रस्ट के साथ कार्य कर रही है। टाटा केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली साझेदारी है। यह बहुआयामी समझौता माताओं, नवजात शिशुओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, कुपोषण और अवरुद्ध विकास को रोकने में सहायक होगा। साथ ही पोषण के लिए आहार विविधता, जल संसाधनों का सतत संरक्षण एवं प्रबंधन, जलवायु-स्मार्ट कृषि और ग्रामीण पशुपालन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

नाम फाउंडेशन राज्य में जल संरक्षण के क्षेत्र में व्यापक कार्य कर रहा है। पूर्व में जलस्रोतों की गाद निकालना, नालों और नदियों की गहराई और चौड़ाई बढ़ाना जैसे कार्य किए गए हैं। जलयुक्त शिवार योजना को राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जो जनआंदोलन बन गई। नाम फाउंडेशन की भागीदारी से विदर्भ और मराठवाड़ा के अल्पवर्षा क्षेत्रों में जल संरक्षण का व्यापक कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें टाटा ट्रस्ट ने भी सहयोग दिया है।

टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी कर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका, जल और स्वच्छता कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य सभी हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। सरकार और टाटा ट्रस्ट ने राज्य के समग्र विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया।

नाम फाउंडेशन के संस्थापक नाना पाटेकर ने भी जल संरक्षण के क्षेत्र में सरकार के साथ कार्य करने के अवसर पर संतोष व्यक्त किया।

बैठक में मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, स्वास्थ्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, महिला एवं बाल विकास सचिव अनुप कुमार यादव, टाटा ट्रस्ट अध्यक्ष नोएल टाटा, नाम फाउंडेशन संस्थापक नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, टाटा ट्रस्ट के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

समझौते का उद्देश्य

यह समझौता स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका में सरकार की प्राथमिकताओं को तकनीक, डिजिटल नवाचार और अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए सहयोग प्रदान करेगा। नागपुर के 6 मान्यता प्राप्त अस्पतालों के साथ समझौते के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को वित्तीय सहायता दी जाएगी तथा मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंतर्गत गंभीर रोगों के लिए सस्ती एवं किफायती चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी।

समझौतों का दायरा

मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना; टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपचार तक पहुंच बढ़ाना; शहरी और दूरस्थ क्षेत्रों में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार; एकीकृत आपातकालीन प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से बेहतर आपात प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।

दो वर्ष से कम आयु के बच्चों में अवरुद्ध विकास, कम वजन और कुपोषण की रोकथाम; किशोरों में कुपोषण और एनीमिया उन्मूलन; गढ़चिरौली जैसे जिलों में विशेष ध्यान के साथ 'टेक-होम राशन' जैसी योजनाओं को सुदृढ़ करना; झीलों का पुनर्जीवन, जलस्रोतों और नदियों की गाद निकालना, भूजल पुनर्भरण बढ़ाना; मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण योजनाओं को लागू करना; जलवायु परिवर्तन अध्ययन के आधार पर कृषि को प्रोत्साहन; वन आधारित और ग्रामीण गैर-कृषि आजीविका को समर्थन; तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल, स्वच्छता और आजीविका को एकीकृत कर समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।

इस वर्ष सांगली में आयोजित होगी 65वीं महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनी

वरिष्ठ कलाकार जी. एस. मजगांवकर को विशेष सम्मान- मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल

मुंबई। कला संचालनालय द्वारा आयोजित '65वीं महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनी (छात्र विभाग)' का आयोजन इस वर्ष सांगली में किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी Kalavishwa College, Shantiniketan Award में 16 से 22 February 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस वर्ष की प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण विद्यालयी छात्रों की विशेष प्रतिभा होगी, ऐसी जानकारी उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री तथा सांगली जिला के पालक मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने दी।

पालक मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने कहा कि राज्य के शासकीय एवं निजी कला संस्थानों के विद्यार्थियों की रचनात्मकता को मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी हर वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाती है। इस वर्ष राज्यभर से 3,490 विद्यार्थियों की 5,680 कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से चयन समिति द्वारा 1,275 उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन हेतु चयन किया गया है। इस प्रदर्शनी के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा वरिष्ठ कलाकार जी. एस. मजगांवकर को उनके दीर्घकालीन कलात्मक एवं शैक्षणिक योगदान के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा।

इस वर्ष से विद्यालयी छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। अब तक यह मंच केवल महाविद्यालयीन विद्यार्थियों तक सीमित था, लेकिन अब शासकीय चित्रकला परीक्षा (ग्रेड परीक्षा) एवं बाल चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयी छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय स्तर के छात्रों को राज्य की मुख्य कला धारा से सीधे जोड़ने का यह निर्णय कला क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। साथ ही यह प्रदर्शनी महाराष्ट्र की समृद्ध कला विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में सहायक होगी।

पालक मंत्री चंद्रकांतदादा पाटिल ने सांगली के कला प्रेमियों, छात्रों एवं शिक्षकों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में इस कला प्रदर्शनी में उपस्थित रहकर इसका आनंद लें।

मनमाड से आईआरसीटीसी की नई आध्यात्मिक यात्रा

टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण, भारत गौरव ट्रेन को मिल रहा अच्छा प्रतिसाद

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा एक नई आध्यात्मिक पर्यटन पैकेज 'टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण' की शुरुआत की जा रही है, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख एवं पवित्र मंदिरों के दर्शन का एक अनूठा अवसर मिलेगा।

यह विशेष रूप से तैयार की गई आध्यात्मिक यात्रा 18 फरवरी 2026 को मनमाड से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन आईआरसीटीसी की विश्वसनीय सेवाओं के अंतर्गत श्रद्धा, संस्कृति और आरामदायक यात्रा का समन्वय प्रदान करेगी।:

यह 12 रातों और 13 दिनों की विशेष आध्यात्मिक यात्रा महाराष्ट्र एवं आसपास के क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों और विरासत प्रेमियों के लिए दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अनूठा अवसर प्रदान करती है।

यात्रियों के लिए मनमाड, नासिक रोड, कल्याण, लोणावला, पुणे, सातारा और मिरज से चढ़ने एवं उतरने की सुविधा प्रदान की गई है

आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई के समूह महाप्रबंधक श्री गौरव झा ने बताया कि यह विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एसी एवं नॉन-एसी पर्यटक ट्रेन यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों–मुरुडेश्वर, गुरुवायूर, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम और महाबलीपुरम–तक ले जाएगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालु मुरुडेश्वर शिव मंदिर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल और महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर, ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे।

इस ट्रेन में इकोनॉमी स्लीपर, स्टैंडर्ड 3एसी और कम्फर्ट 2एसी श्रेणियाँ उपलब्ध हैं तथा यह लगभग 750 यात्रियों की क्षमता रखती है। यात्रियों के लिए मनमाड, नासिक रोड, कल्याण, लोणावला, पुणे, सातारा और मिरज से चढ़ने एवं उतरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

यह यात्रा ऑल-इन्क्लूसिव पैकेज के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसमें शामिल हैं: एसी एवं नॉन-एसी कोच में रेल यात्रा, बजट होटलों में ठहराव (डबल/ट्रिपल/क्वाड शेयरिंग), संपूर्ण यात्रा के दौरान शुद्ध शाकाहारी भोजन, एसी एवं नॉन-एसी स्थानीय परिवहन एवं दर्शनीय स्थल भ्रमण,यात्रा बीमा एवं समर्पित आईआरसीटीसी टूर मैनेजर्स की सेवाएँ आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. ए. के. सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सावधानियाँ सुनिश्चित की गई हैं।

इस यात्रा का मूल्य इकोनॉमी क्लास के लिए 23,370, स्टैंडर्ड 3एसी के लिए 36,990 तथा कम्फर्ट 2एसी के लिए 48,760 निर्धारित किया गया है। बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए यात्री 8287931886 पर संपर्क कर सकते हैं या bgtmumbai@irctc.com पर ईमेल भेज सकते हैं

यह पहल आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ क्षेत्रीय संपर्क को सशक्त बनाती है और यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदायक तरीके से दक्षिण भारत की आध्यात्मिक विरासत से जोड़ती है।

जनसहभाग से नवी मुंबई में स्वच्छता अभियान, 'हिंद-दी-चादर' के अवसर पर सेवाभावी श्रद्धांजलि

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

'हिंद-दी-चादर' के अवसर पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का स्मरण करते हुए विविध जनकल्याणकारी उपक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 10 से 25 ईर्ल्हि के दौरान नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में 124 विशेष स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन की शुरुआत की गई है।

इसी तरह घनकचरा प्रबंधन विभाग के माध्यम से भी 'हिंद-दी-चादर' के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज बेलापुर, नेरूल, वाशी, कोपरखैरणे तथा घणसोली विभाग कार्यालय क्षेत्रों में आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार एवं घनकचरा प्रबंधन विभाग के उप आयुक्त डॉ. अजय गडदे के नियंत्रण में व्यापक जनसहभाग से सघन स्वच्छता अभियान चलाए गए।

इसमें सेक्टर 8 सीबीडी बेलापुर स्थित गुरुद्वारा के सामने के परिसर में जनसहभाग से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी प्रकार सेक्टर 19 नेरूल स्थित गुरुद्वारा परिसर तथा कोपरखैरणे गुरुद्वारा परिसर में भी सघन स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। इन अभियानों में गुरुद्वारों से जुड़े नागरिकों ने भी सक्रिय सहभागिता की। सायन-पनवेल हाईवे पर परिवहन बस स्टॉप परिसर में दिन-रात भारी भीड़ रहती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वहां जनसहभाग से विशेष सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में महानगरपालिका के स्वच्छता अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छताकर्मी तथा टिळक कॉलेज के एनएसएस विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान 1 डंपर कचरा एकत्र कर उसे घनकचरा प्रकल्प स्थल तक ले जाया गया।

इसी प्रकार 'हिंद-दी-चादर' के अवसर पर रामनगर दिघा से वोडाफोन कंपनी तक की मुख्य सड़क के दोनों ओर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही श्री मनोशी कॉम्प्लेक्स सोसायटी के पीछे की गली तथा घणसोली स्थित सेंट्रल पार्क परिसर में भी सघन स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।

'हिंद-दी-चादर' के अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े उपक्रमों के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के अद्वितीय कार्यों को सेवाभावी गतिविधियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना युवाओं को करियर में अग्रिम पंक्ति में ले जाएगी - सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य के सर्वाधिक मेधावी विद्यार्थियों का चयन मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत किया जाता है। इस योजना के माध्यम से प्राप्त प्रशासनिक कार्य अनुभव युवाओं को उनके भविष्य के करियर में अग्रणी बनाएगा, ऐसा प्रतिपादन राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे ने किया।

डॉ. नारनवरे महाराष्ट्र लोक भवन, मुंबई में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर 7वीं मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में शासकीय कार्यालयों में कार्यरत 60 मुख्यमंत्री सहयोगी युवाओं से उन्होंने संवाद किया।

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के माध्यम से युवाओं को जिलाधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालयीन विभाग प्रमुख, सचिव, मंत्री तथा मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है।

डॉ. नारनवरे ने कहा कि मुख्यमंत्री सहयोगी के रूप में चयनित युवाओं को तकनीक को अपनाना चाहिए, लेकिन केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक सीमित न रहते हुए उससे आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में अपनी रुचि के विषय का चयन कर उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना आवश्यक है।

डॉ. नारनवरे ने मुख्यमंत्री युवा सहयोगियों को लोक भवन में होने वाले विधायी, संसदीय, आदिवासी विकास, शैक्षणिक तथा औपचारिक कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

योजना की मुख्य संप्रेषण अधिकारी प्रिया खान ने बताया कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना चयनित युवाओं के अनुभव को समृद्ध करने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री फेलो को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई द्वारा सार्वजनिक नीति विषय में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

बॉम्बे हाई कोर्ट की विजय माल्या को दो टूक- पहले भारत लौटो, फिर होगी सुनवाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को फटकार लगाते हुए कहा कि जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बचते हुए वे न्यायसंगत राहत की मांग नहीं कर सकते। अदालत ने माल्या को भारत लौटने के अपने इरादे को स्पष्ट करने का अंतिम मौका दिया।

माल्या की याचिका में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और उनकी भगोड़ा घोषित किए जाने को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ विजय माल्या की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और उन्हें भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि वह इस बात को दर्ज करने के लिए इच्छुक है कि माल्या अदालत के अधिकार क्षेत्र से बच रहे हैं और इसलिए वे अपनी याचिका में राहत की उम्मीद नहीं कर सकते।

अदालत ने कहा, 'आपको लौटना होगा। यदि आप नहीं लौटते हैं, तो हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। आप अदालती प्रक्रिया से बच रहे हैं, इसलिए जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बचते हुए आप न्यायसंगत राहत की मांग नहीं कर सकते। फिर भी, निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए, हम मामले को खारिज नहीं कर रहे हैं और आपको एक और मौका दे रहे हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि सरकार भारत में वांछित आर्थिक भगोड़ों को मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हालांकि इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, सरकार विजय माल्या और ललित मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल नामों सहित आर्थिक अपराधियों की वापसी के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम भारत में कानून द्वारा वांछित और भगोड़े लोगों को देश में वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, लेकिन हम उन्हें वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि वे यहां की अदालतों में मुकदमे का सामना कर सकें। माल्या और मोदी दोनों पर भारत में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 31 अक्टूबर, 2025 तक, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत कुल 15 व्यक्तियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इनमें से नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप 26,645 करोड़ रुपये का मूलधन का नुकसान हुआ। 31 अक्टूबर, 2025 तक इन ऋणों पर अर्जित ब्याज 31,437 करोड़ रुपये है, जबकि अपराधियों से 19,187 करोड़ रुपये वसूल किए जा चुके हैं।

'दिलखुलास' और 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी की विशेष मुलाकात

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी की 'सांस्कृतिक कार्य विभाग की कार्यप्रणाली तथा राज्य में किलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लिए गए नीतिगत निर्णय' इस विषय पर विशेष मुलाकात, सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय द्वारा निर्मित 'दिलखुलास' और 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमों में प्रसारित की जाएगी।

छत्रपति शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन तथा किलों की मूल भव्यता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर नियोजित और प्रभावी उपाय लागू किए जा रहे हैं। विभाग राज्य की ऐतिहासिक विरासत, किलों, स्मारकों और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए रणनीतिक योजना, वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा विभिन्न शासकीय और विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

इस साक्षात्कार में सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण और संवर्धन हेतु जनजागरूकता गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी भी दी है।

'दिलखुलास' कार्यक्रम में यह विशेष मुलाकात मंगलवार 17 और बुधवार 18.02.2026 को सुबह 7.25 से 7.40 तक ऑल इंडिया रेडियो के सभी केंद्रों से प्रसारित की जाएगी तथा 'न्यूज़ ऑन एयर' मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगी। इसी प्रकार 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रम में यह मुलाकात मंगलवार 17.02.2026 को रात 8.00 बजे दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल पर प्रसारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह साक्षात्कार सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय के आधिकारिक सामाजिक माध्यमों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस साक्षात्कार का संचालन प्रस्तोता डॉ. मृण्मयी भाजक ने किया है।

सम्पादकीय

आठ लाख से ज्यादा लोग लापता, दिल्ली के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, तंत्र की लापरवाही दे रही है अपराधियों को मौका

देश भर में हर साल बड़ी संख्या में लोग लापता हो जाते हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और लड़कियां शामिल होती हैं। इस वर्ष जनवरी के पहले पखवाड़े में दिल्ली से आठ सौ से अधिक लोगों के लापता होने की खबरों ने इस मसले की गंभीरता को फिर से उजागर किया है। मगर हैरत की बात है कि इस आपराधिक समस्या से निपटने के लिए अब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकीकृत प्रयास होते नजर नहीं आए हैं। यहां तक कि लापता होने की घटनाएं और उनमें से कितने लोगों को ढूंढ़ लिया गया तथा ऐसे मामलों के पीछे किसका हाथ था, इसका एकीकृत राज्यवार ब्योरा भी मुश्किल से दर्ज हो पाता है।

यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस मसले पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह इस बात का पता लगाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे किसी देशव्यापी गिरोह या राज्य-विशिष्ट समूह का हाथ तो नहीं है। इसके लिए तमाम राज्यों से ऐसे मामलों की संख्या और कार्रवाई का ब्योरा संकलित कर उनका विश्लेषण करने का निर्देश भी दिया गया है।

गौरतलब है कि देश भर में बच्चों की गुमशुदगी के मामलों से संबंधित आंकड़ों के संकलन के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर सभी राज्य ऐसी घटनाओं का ब्योरा दर्ज करा सकते हैं। मगर, इस प्रक्रिया में भी सरकारी तंत्र की उदासीनता साफ देखी जा सकती है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में खुद यह बात स्वीकार की है कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और उनसे संबंधित अभियोजन से जुड़े आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।

दरअसल, पिछले वर्ष दिसंबर में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को लापता बच्चों के सिलसिले में छह साल के राष्ट्रव्यापी आंकड़े उपलब्ध कराने और ऐसे आंकड़ों के संकलन में राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने को कहा था। इससे पहले राज्यों को बच्चों की गुमशुदगी के मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश भी दिया गया था। इसके बावजूद अगर राज्यों की ओर से संबंधित ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो इससे सरकारी तंत्र में व्यवस्थागत खामियों का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

इसमें दोराय नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में विशेषकर बच्चों, महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की घटनाएं जितनी बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं, उससे इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे देशव्यापी या राज्य स्तरीय गिरोहों का हाथ हो सकता है। इसलिए इस बात की गहन जांच-पड़ताल जरूरी है कि लापता होने की ज्यादातर घटनाओं में किसी तरह कोई समानता तो नहीं है! मगर यह तभी संभव होगा, जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों से जुड़े आंकड़ों का संकलन हो पाएगा।

इस मसले की गंभीरता का अंदाजा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की एक रपट से लगाया जा सकता है, जिसके मुताबिक, वर्ष 2023 में देश भर में आठ लाख से ज्यादा लोग लापता हुए थे। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यह समस्या ज्यादा गंभीर है। ऐसे में जरूरी है कि हर राज्य अपनी जिम्मेदारी को समझे और लापता होने के मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर कहीं कोई लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा कायम रह सके।

संसद बनी बंधक- संविधान का अपमान कौन कर रहा है?

वर्ष -2026 का बजट सत्र हल्ले-गुल्ले और अराजकता की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ बजट के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को उठाए जाने का प्रयास हो रहा है। स्थितियां इतनी विकट हैं कि संसदीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री लोकसभा में उत्तर नहीं दे सके और राष्ट्रपति का अभिभाषण बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 97 मिनट लंबा और प्रभावशाली उत्तर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा की गई सभी टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन देश के स्वर्णिम भविष्य और विकास की दिशा को भी दर्शाता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हंगामा करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने के बाद जब समय आने पर राहुल गांधी को बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने विषय से इतर जाकर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक कोट करते हुए चीनी घुसपैठ का पुराना मुद्दा उछालने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियमों के अंतर्गत व्यवस्था दिए जाने के बाद भी राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे। यह एक आश्चर्यजनक व्यवहार है कि नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के स्थान पर पुराने मुद्दे उठाए और उनको भी आपत्तिजनक रूप से रखकर देश की सेना और सदन का अपमान करे। लोकसभा में कांग्रेस तथा इंडी गठबंधन की

महिला सांसदों ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने की योजना बनायी और लोकसभा अध्यक्ष को प्रधानमंत्री से सदन न आने का अनुरोध करना पड़ा वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना ये है कि यही लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बाते करते हैं।

राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग न लेकर विपक्षी दलों ने न केवल राष्ट्रपति पद का अपमान किया है अपितु एक गरीब परिवार से निकलकर आई आदिवासी महिला का भी अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी व कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को ग़द्दार कहने पर भी राहुल गांधी घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया है । कांग्रेस छोड़कर कितने ही लोग निकले हैं किसी और को तो ग़द्दार नहीं कहा, ये सिख हैं इसलिए कहा, ये सिखों का, गुरुओं का अपमान था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा में चेयर पर कागज फेकें गए जब असम के सदस्य चेयर की कुर्सी पर विराजमान थे क्या यह असम का अपमान नहीं? जब आंध्र प्रदेश के एक दलित सदस्य चेयर की कुर्सी पर बैठे थे तब उन पर भी कागज फेंके गए क्या यह एक दलित बेटे और संविधान का अपमान नहीं है ?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आखिर कांग्रेस उनके लिए कब्र खुदेगी का नारा क्यों देती है ? हमने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 से हटाई इसलिए या हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा है इसलिए? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने के सपने देखती है? आजकल मोहब्बत की दुकान खोलने वाले 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। हमने नार्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो साया बना रहता था वहां शांति और विकास की राह अपनाई इसलिए वह मोदी की कब्र खोद रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियो को घर में घुसकर मारते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और इसलिए वे मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये जो उनके भीतर नफरत भरी हुई है मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है, उसका कारण है किकांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि कोई और क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, ये तो हमारा पैतृक अधिकार था इसलिए वे हताशा में मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे जोड़ा कि कांग्रेस को ये सहन नही हो रहा हे कि जो समस्याएं उसने 60 सालो में पाल- पोस कर बड़ी की थीं मोदी उनका एक-एक करके समाधान क्यों कर रहा है? कांग्रेस को ये सब पसंद नहीं आ रहा है इसलिए अब कांग्रेस के नेता मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन और फिर अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौते हुए उनके विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और समझौते कर रही है। कांग्रेस को भी यहअवसर मिला था, उन्होंने यह क्यों नही कर दिखाया?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से कांग्रेस, लेफ्ट व डीएमके सहित टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला और उन्होंने बंगाल की टीएसमी सरकार को देश की सबसे निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि यह लोग अपने अंदर नहीं झाकते अपितु हमको यहां बैठकर उपदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद सदानंद मास्टर के भाषण का संज्ञान लेते हुए वैचारिक सहिष्णुता की चर्चा की, ज्ञातव्य है कि सदानंद मास्टर के दोनों पैर वामपंथी विचारधारा के लोगों ने निर्ममता से केवल उनकी विचारधारा अलग होने के कारण काट दिए थे।

संसद के वर्तमान सत्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने जो रवैया अपनाया है उसने देश के वास्तविक मुद्दों को उठाने का एक सुनहरा अवसर खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा को घेरने के बजे उन्होंने भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी को ही अपने ऊपर आक्रमण करने का अवसर दे दिया है। भाजपा अब सिख व दलित सांसदों के अपमान का राजनैतिक लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेगी। भाजपा चुनाव वाले राज्यों में विरोधी दलों के संसदीय आचरण को भी मुद्दा बनाएगी।

जब 'मैं' भारी पड़ता है 'हम' पर तब स्वार्थ कहां तक जायज है सफलता और प्रतिस्पर्धा, आधुनिक जीवन में रिश्तों की बदलती परिभाषा

निजी स्वार्थ मनुष्य के स्वभाव का एक ऐसा पक्ष है, जो जन्म से उसके साथ चलता है। स्वयं की सुरक्षा, प्रगति और पहचान की चाह स्वाभाविक है। यही स्वार्थ मनुष्य को परिश्रम करना, आगे बढ़ना और अपने लिए बेहतर जीवन गढ़ना सिखाता है। मगर जब यही भावना सीमाएं लांघने लगे, तब यह समाज के लिए चिंता का विषय बन जाती है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय- हर क्षेत्र मंर आगे निकलने की होड़ है। इस होड़ में कई बार व्यक्ति अपने लाभ को ही सर्वोच्च मान लेता है और दूसरों के हिस्से की जमीन भी अपने पांव तले दबाने लगता है। यही वह बिंदु है जहां स्वस्थ स्वार्थ अस्वस्थ बन जाता है। ऐसा स्वार्थ सफलता का भ्रम तो रचता है, पर भीतर से मनुष्य को खोखला कर देता है।

स्वार्थ का प्रभाव केवल व्यक्तिगत आचरण तक सीमित नहीं रहता। यह धीरे-धीरे रिश्तों में प्रवेश करता है। आज अनेक संबंध सुविधा और उपयोगिता पर टिके दिखाई देते हैं। जब तक व्यक्ति काम का है, तब तक वह अपना है; और काम निकलते ही दूरी बन जाती है। यह सोच परिवारों में दरार, मित्रता में अविश्वास और समाज में असंवेदनशीलता को जन्म देती है। छात्र जीवन में जैसे ही किसी एक को बेहतर अंक या अवसर मिल जाता है, दूरी अपने आप बन जाती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रेरणा देती है, लेकिन जब स्वार्थ हावी हो जाएं, तब मित्रता बोझ बन जाती है, जो समय की कसौटी पर ठिक नहीं पाती।

कार्यस्थलों पर 'टीमवर्क' यानी 'सामूहिक भावना के साथ काम' की बातें होती हैं, लेकिन श्रेय लेने की होड़ बनी रहती है। किसी सहकर्मी के विचार को अपना बताकर प्रस्तुत करना, किसी के अच्छे काम को खराब बताना, सही को गलत कहना और सफलता मिलते ही आगे बढ़ जाना- ये व्यवहार संस्थानों को भीतर से कमजोर कर देते हैं। जहां भरोसा नहीं होता, ईर्ष्या हावी होती है, वहां कार्यक्षमता भी धीरे-धीरे गिरने लगती है। स्वार्थ भले ही व्यक्ति को अस्थायी लाभ दिला दे, पर कार्य-संस्कृति को स्थायी नुकसान पहुंचाता है।

स्वार्थ का सबसे संवेदनशील और पीड़ादायक रूप परिवार में देखने को मिलता है। संपत्ति के बंटवारे में भाई-भाई का दुश्मन बन जाना, बुजुर्गों को बोझ समझना या रिश्तों को सुविधा के तराजू पर तौलना- ये दृश्य आज आम होते जा रहे हैं। परिवार वह स्थान होना चाहिए, जहां निस्वार्थ होना सबसे अधिक हो, लेकिन जब वही स्थान स्वार्थ का शिकार बन जाए, तो समाज की नींव हिलने लगती है।

माता-पिता का प्रेम इस संसार का सबसे निस्वार्थ भाव है। वे अपनी इच्छाएं, सुख-सुविधाएं और कई बार अपने सपने तक बच्चों के भविष्य के लिए त्याग देते हैं। जीवनभर देते रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। विडंबना यह है कि ऐसे निस्वार्थ प्रेम के बावजूद कुछ बच्चे स्वार्थी हो जाते हैं। पढ़ाई पूरी होते ही माता-पिता से दूरी बना लेना, उनकी जरूरतों को बोझ समझना या उन्हें अकेला छोड़ देना- ये दृश्य आज चुभते हुए सच बन चुके हैं। यह स्वार्थ केवल माता-पिता को नहीं, मानवीय संवेदना को भी चोट पहुंचाता है।

इन उदाहरणों के बीच हमारे सैनिक निस्वार्थ भावना का जीवंत प्रतीक हैं। वे अपने परिवार, आराम और कभी-कभी अपने प्राण तक देश के लिए समर्पित कर देते हैं। सीमा पर खड़ा सैनिक यह नहीं सोचता कि उसे क्या मिलेगा, वह केवल यह सोचता है कि देश सुरक्षित रहे। जब हम अपने छोटे-छोटे लाभ के लिए रिश्तों और जिम्मेदारियों से समझौता कर लेते हैं, तब सैनिकों का त्याग हमें आईना दिखाता है। उनका बलिदान याद दिलाता है कि सच्चा कर्तव्य वही है, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर निभाया जाए।

एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी में एकलव्य ने बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और लगन से धनुर्विद्या सीखी, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए स्वार्थवश एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, जिससे स्वार्थ की सीमाओं और पक्षपात की तस्वीर उजागर हुई। ऐसे प्रसंगों से हमें स्पष्ट संदेश मिलता है कि स्वार्थ न केवल दूसरों का नुकसान करता है, बल्कि नैतिकता, न्याय और रिश्तों की नींव को भी कमजोर कर देता है।

प्रश्न यह नहीं कि हम स्वार्थी हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि हमारा स्वार्थ रिश्तों को जोड़ रहा है या तोड़ रहा है। जिस दिन हम अपने लाभ की सीमा वहां रोक देंगे, जहां से दूसरों की पीड़ा शुरू होती है, उसी दिन स्वार्थ मानवता में बदल जाएगा। हालांकि कहना मुश्किल है कि स्वार्थ पूरी तरह त्याज्य है। आत्मसम्मान की रक्षा करना, अपने अधिकारों के लिए खड़े होना और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना- ये सब स्वार्थ नहीं, बल्कि विवेक हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब विवेक का स्थान केवल लाभ-लालसा ले लेती है।

संतुलन ही समाधान है- ऐसा संतुलन जिसमें 'मैं' सुरक्षित रहे और 'हम' भी जीवित रहें। इतिहास और वर्तमान- दोनों इस सत्य के साक्षी हैं कि केवल अपने लिए जीने वाले लोग क्षणिक रूप से सफल हो सकते हैं, पर समाज उन्हें याद नहीं रखता। समाज उन्हें स्मरण करता है, जिन्होंने अपने स्वार्थ की सीमा वहीं रोक दी, जहां दूसरों की पीड़ा शुरू होती है। ऐसे लोग पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनते हैं।

आज आवश्यकता है स्वार्थ की ऐसी नई परिभाषा गढ़ने की, जो आत्मविकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच सेतु बने। अगर व्यक्ति यह समझ ले कि समाज के बिना उसका अस्तित्व अधूरा है, तो स्वार्थ स्वतः ही मानवीय हो जाएगा। आखिरकार स्वार्थ समस्या नहीं है, समस्या है उसकी दिशा। सही दिशा में प्रवाहित स्वार्थ समाज को आगे बढ़ाता है और गलत दिशा में बहता स्वार्थ उसे भीतर से तोड़ देता है। चुनाव हमारे हाथ में है- हम अपने स्वार्थ से केवल ऊंचे बनना चाहते हैं या व्यापक भी!

जेन-जेड की डिजिटल दुनिया, ताकत या कमजोरी नई पीढ़ी को हकीकत से दूर ले जा रही तकनीक

दुनियाभर में युवाओं की नई पौध कहीं अधिक प्रखर और त्वरित कदमों से आगे बढ़ने वाली पीढ़ी है। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के दौर की इस पीढ़ी को आजकल 'जेन-जेड' कहा जा रहा है। यही वह नई युवा शक्ति है, जो अपने-अपने देशों में अन्याय और विसंगतियों के विरुद्ध खड़ी हो रही है। कुछ समय पहले पूरी दुनिया ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में उन प्रदर्शनों को देखा, जिनमें हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। उस समय ऐसा लगा कि बहुत कुछ बदल जाएगा। जो विसंगतियां हैं, अब वे खत्म होंगी। चाहे वह भ्रष्टाचार हो या नेताओं का परिवारवाद या फिर महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या। मगर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और इन देशों में ढर्रा वही रहा, जो पहले था। सत्ता परिवर्तनों के बावजूद कोई खास बदलाव सामने नहीं आया।

नई युवा शक्ति का असमानता और अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होना उन देशों के लिए असरदार हो सकता है, जहां स्थिति सचमुच बेहद खराब है और जहां अर्थव्यवस्था जर्जर हो रही है। मगर दिक्कत यह है कि कृत्रिम मेधा और सोशल मीडिया से प्रभावित यह पीढ़ी तत्काल सब कुछ दुरुस्त कर लेना चाहती है। मगर सच तो यह है कि अचानक सड़कों पर उतर जाने से रातों-रात व्यवस्था नहीं बदल जाती। यह पीढ़ी अपनी ताकत का धैर्य और सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करे, तो दुनिया में जो बदलाव वे चाहते हैं, वह संभव हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस पीढ़ी की सार्थकता और उसकी ताकत पर दुनिया का भरोसा कायम हो सकता है। मगर अभी ऐसा हुआ नहीं है। इस समय बड़ी चुनौती यह है कि डिजिटल दुनिया से प्रभावित इस शक्ति को अगर सही दिशा नहीं मिली, तो इससे उनका ही नुकसान हो सकता है।

भारत में इस युवा पीढ़ी को सार्थक निवेश के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश इनका साथ लेकर प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर होना चाहता है। मगर, ये उम्मीदें आगे कितनी सच होंगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। देश की युवा आबादी कार्ययोग्य है, लेकिन उन्हें काम देने की बजाय अनुकंपा पर जीने की राह दिखाई जा रही है। अगर वे जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए दूसरे देशों की ओर पलायन करते हैं, तो वहां से उन्हें किस तरह से स्वदेश वापस भेजा गया है, इसे सभी ने देखा है। अपने देश में तो रोजगार की गुंजाइश बढ़ नहीं रही, ऐसे में युवा करे, तो क्या करें। वहीं इनके सही राह से भटक जाने का जो जोखिम है, इसे कौन समझेगा।

युवा देश की अमूल्य निधि होते हैं। उनके प्रखर और विकासोन्मुख होने की बात कही जाती है। मगर अभी दुनिया के कई देशों में अनुसंधान का निष्कर्ष यह बताता है कि आधुनिक तकनीक अपनाने वाली इस पीढ़ी की मेधा शक्ति पिछली पीढ़ी से कम है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका कारण यह बताया जाता है कि 'जेन-जेड' कहलाने वाली यह पीढ़ी डिजिटल तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर है। स्वयं खोज करने या अनुसंधान करने की बजाय उन्हें पहले से तैयार सब चीजें चाहिए। कई बार उनमें मौलिकता नहीं दिखाई पड़ती। उनमें कितनी संभावनाएं हैं, यह सामने आना अभी बाकी है। कहा जा रहा है कि भारत कृत्रिम मेधा और डिजिटल दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह साफ है कि नई पीढ़ी मेधा और स्मृति के मामले में पिछली पीढ़ी जितनी भी नहीं दिखाई देती है।

समस्या सुलझाने का उनका तरीका त्वरित बेशक हो, लेकिन वह ठोस और व्यावहारिक नहीं होता। बड़े-बुजुर्ग जटिल से जटिल समस्याओं का धीरज से सामना करते हुए न केवल उन्हें सुलझाने में कामयाब हो जाते थे, बल्कि एक नया पैमाना भी बना देते थे। वहीं आज की युवा पीढ़ी संक्षिप्त वीडियो से स्वयं को प्रशिक्षित करने और इसी से रास्ता तलाशने में लगी रहती है। अध्यापकों के साथ आमने-सामने बातचीत अब होती नहीं। नतीजा बच्चों की बौद्धिक क्षमता घटने लगी है।

देश में तकनीक के अधिक इस्तेमाल के कारण किसी में स्वयं खोज करने की पहल नहीं दिखाई देती। शोध विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले पचास- साठ साल में जैसे-जैसे भारत सहित पूरी दुनिया में तकनीक का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में बढ़ा है, बच्चों में सीखने की क्षमता घट गई है। मगर जो बच्चे प्रौद्योगिकी का कम या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, उनके परिणाम उन बच्चों से बेहतर हैं, जो डिजिटल सुविधा पर निर्भर हैं।

भारत समेत पूरी दुनिया में कृत्रिम मेधा का बोलबाला हो गया है। सब जगह कागज रहित कार्य संस्कृति विकसित होने लगी है। दूसरी ओर इसी नई तकनीक का नतीजा है कि अब पुस्तकों के जरिए कम और स्मार्ट फोन, लैपटाप एवं कंप्यूटर पर शिक्षा देने का चलन बढ़ रहा है। कारण यह है कि युवा पीढ़ी यानी जेन-जी डिजिटल ताकत का इस्तेमाल करती है। वे कहीं अधिक आत्मविश्वासी हैं। उनको लगता है कि वे हर चीज जानते हैं। उनके पास सभी सूचनाएं उपलब्ध हैं। बच्चों को हम स्मार्टफोन तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी मौलिकता कम होती जा रही है। डिजिटल दुनिया की इस अपार ताकत ने एक नए खतरे को जन्म दिया है। अब कहा जा रहा है कि तकनीक में तरक्की तो कीजिए, लेकिन इस पर नियंत्रण भी रखिए। विशेषज्ञों ने इस पूरे परिदृश्य पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि एक समय में पूरी दुनिया इस डिजिटल ताकत से बेहद प्रभवित थी। अब उसका असर घटने लगा है। कुछ देश तो तकनीक के बेतहाशा उपयोग से अब पीछे हटने लगे हैं। स्वीडन ने हाल ही में विद्यालयों में डिजिटल उपकरणों को हटा कर फिर से कागज-कलम और किताबों की ओर लौटने का फैसला किया है। फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फिनलैंड जैसे देशों में स्कूलों में लैपटाप और टैबलेट के इस्तेमाल को अब सीमित किया जा रहा है।

यूनेस्को की एक रपट के मुताबिक, शिक्षा में तकनीक का अधिक इस्तेमाल ठीक नहीं है। इसे सीखने में मदद करने तक ही सीमित रखना चाहिए, न कि पथ निर्देशक बनने देना चाहिए। इसके नकारत्मक प्रभाव अब सामने आ रहे हैं। हाल में गाजियाबाद में जो घटना हुई है, उससे भी सबक लिया जा सकता है, जहां तीन नाबालिग बहनों ने आभासी दुनिया में गुम होकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। यह घटना एक उदाहरण भर है। पहले भी डिजिटल लत के कारण ऐसी घटनाएं होती रही हैं।

दरअसल, हमारी नई पीढ़ी सपने में जीने लगी है। उनकी ताकत डिजिटल की बैसाखियों पर निर्भर है। जो ताकत दुनिया को सशक्त करने के लिए बनाई गई थी, वह नौजवानों को एक काल्पनिक जगत में कैद कर रही है। अब वे घंटों कंप्यूटर के सामने या स्मार्टफोन लेकर बैठे रहते हैं। युवा आभासी दुनिया को सच मान कर जीवन की वास्तविकताओं से दूर जाकर एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं, जिसका वजूद उनकी कल्पना में तो है, लेकिन असल जिंदगी में कहीं नहीं। नई पीढ़ी यानी 'जेन-जेड' के उभरने और संवरने से पहले ही डिजिटल की ताकत उसे यथार्थ से दूर ले जा रही है। इस पर नियंत्रण तो किसी सीमा तक करना ही होगा, ताकि वह नई पीढ़ी के लिए चुनौती न बन जाए।

जिलाधिकारी ने तहसील बारा पहुंचकर तहसील परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया

जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से निस्तारित करने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने गुरूवार को तहसील बारा पहुंचकर तहसील परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने तहसील परिसर में स्थित उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के कार्यालय सहित अन्य कार्यालयों एवं पटल का भ्रमण कर प्रशासनिक कार्यों, अभिलेखों का रख-रखाव, पत्राचार, पुराने प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति, जनसुनवाई व्यवस्था और कार्मिकों की कार्यप्रणाली की जांच करते हुए आवश्यक निर्देश दिये हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से उनसे सम्बंधित कार्यों के बारे में जानकारी ली और सभी सम्बंधित अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तहसील परिसर एवं सभी कक्षों में साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था और पत्रावलियों के रखरखाव को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालयी अनुशासन और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने जनता दर्शन की सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से यथोचित निर्णय लेते हुए प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए है। लोगो को एक ही कार्य के लिए तहसील का बार-बार चक्कर न लगाना पड़े, इसलिए शिकायतों के निस्तारण की मानीटरिंग को और प्रभावी बनाये जाने के लिए कहा। कहा कि सभी जनशिकायती पत्रों में शिकायतकर्ता का नाम मोबाइल नम्बर अवश्य लिखा रहे तथा सभी प्रकरणों में फीडबैक अवश्य लिया जाये।

उन्होंने उपजिलाधिकारी बारा से सभी पुराने लम्बित प्रकरणों को नियमित सुनवाई करते हुए प्राथमिकता पर निस्तारित करने के लिए कहा है। उन्होंने उप जिलाधिकारी कोर्ट में सबसे पुराने समय से लम्बित फाइलों की जानकारी लेते हुए 2013 से लम्बित सबसे पुरानी फाइल को निकलवाकर देखा तथा उपजिलाधिकारी बारा को उसकी सुनवाई कर निस्तारित किए जाने के लिए कहा। उन्होंने पांच वर्ष व 3 वर्ष से अधिक पुराने समय से लम्बित फाइलों की छंटनी कराये जाने तथा ऐसे पुराने समय से लम्बित प्रकरणों में नियमित सुनवाई करते हुए इन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने सभी फाइलों को रजिस्टर में अवश्य दर्ज करने एवं लम्बित तथा निस्तारित प्रकरणों की फाइलों को अलग-अलग कर सभी को सुव्यवस्थित ढंग से रखे जाने के लिए कहा।

जिलाधिकारी ने तहसीलदार से सम्बंधित कोर्ट का निरीक्षण किया तथा पत्रावलियों का रख-रखाव एवं उनके निस्तारण की स्थिति को देखा। उनके द्वारा सबसे अधिक समय से लम्बित प्रकरण के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि तहसीलदार कोर्ट में सबसे पुरानी लम्बित फाइल वर्ष 2014 की धारा-35 म्यूटेशन से सम्बंधित है, जिसपर जिलाधिकारी ने फाइल को निकलवाकर देखा तथा सम्बंधित प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने तत्पश्चात नायब तहसीलदार कोर्ट बारा, शंकरगढ़ का भी निरीक्षण किया तथा वहां पर पांच साल व तीन साल से अधिक सभी पुराने लम्बित प्रकरणों को एक साथ सूचीबद्ध करते हुए नियमित सुनवाई पर लगाकर ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के लिए कहा है। उन्होंने अंश निर्धारण, वरासत, धारा-32/38, धारा-24 आदि से सम्बंधित अविवादित प्रकरणों में सम्बंधित पक्षों की सुनवाई करते हुए तत्काल निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया है।

तत्पश्चात जिलाधिकारी ने अभिलेखागार, संग्रह अनुभाग सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने अभिलेखागार में परगना अरैल ग्राम सेमरा कला के बस्ते को खुलवाकर देखा, जिसमें वर्षवार खसरा, खतौनी, 41 एवं 45 अभिलेखों का उचित रख-रखाव नहीं पाया गया, जिसपर जिलाधिकारी ने पुराने अभिलेखों की टेपिंग/बाइडिंग कराकर उन्हें सुरक्षित ढंग से रखे जाने के लिए निर्देश दिए है। उन्होंने संग्रह अनुभाग का निरीक्षण किया तथा तहसील के सबसे बड़े बकायेदारों की जानकारी लेते हुए वसूली न होने की दशा में बकायेदारों की सम्पत्ति का मूल्यांकन के पश्चात उसकी नीलामी की कार्यवाही करने के लिए कहा है।

उन्होंने सभी पटल सहायकों को समय से उपस्थित होने तथा उनसे सम्बंधित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में भवनों के जर्जर हिस्सों के मरम्मतीकरण हेतु व्यय का आगणन कराकर प्रस्ताव भेजे जाने के लिए कहा है। उन्होंने तहसील परिसर में पेयजल व साफ-सफाई की अच्छी व्यवस्था कराये जाने के लिए कहा है।

तत्पश्चात जिलाधिकारी ने बारा तहसील स्थित ग्राम टिकरीकला में अमृत सरोवर की खुदाई के कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने सम्बंधित लेखपाल से तालाब के वास्तविक क्षेत्रफल एवं सीमाओ की जानकारी लेते हुए तालाब की पैमाइश कराये जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पैमाइश में यदि अभिलेखों में दर्ज तालाब के क्षेत्रफल में कुछ कमी पायी जाये तो अभिलेखों में दर्ज तालाब के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का सीमांकन करते हुए अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाये। उन्होंने अमृत सरोवर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य को निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने तथा मॉडल अमृत सरोवर के रूप में विकसित कराये जाने के लिए कहा है।

52 वर्ष से प्रतिदिन रूद्राभिषेक कर रहे स्वामी रामाश्रम शास्त्री

कहा कि महादेव के समान संसार में कोई दूसरा देवता नहीं

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। 68 वर्षीय अखिल भारतीय दण्डी संन्यासी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पीठाधीश्वर स्वामी रामाश्रम शास्त्री स्वामी महराज है जो 52 वर्ष से प्रतिदिन रूद्राभिषेक करते है। इनका कहना है कि सभी देवताओं में भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ है इसलिए इनको महादेव कहा गया है। उन्होंने बताया कि शिव पुराण में लिखा है कि सबसे पहले भगवान शिव की लिंग के रूप में उत्तपत्ति हुई है उसके बाद भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु की। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक करने से सभी समस्याएं खत्म होती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

पीठाधीश्वर स्वामी रामाश्रम शास्त्री स्वामी महराज 68 वर्ष के है। उन्होने बताया कि 16 वर्ष की अवस्था में संन्यास लें लिया था। 1008 स्वामी मुनीषाश्रम जी महराज से दीक्षा लिया। वर्तमान में श्रृंगवेरपुर धाम के पास दिव्य नारायण सेवा आश्रम, पुरूषोत्तम घाट, गढवा, अखराजपुर में गंगा तट पर आश्रम स्थित है। जहां प्रतिदिन शिष्यों के साथ भगवान शिव का अभिषेक

होता है।

उन्होंने बताया कि भगवान शिव का गंगाजल, दूध, दही, शहद, शंकर, घी, गन्ने का रस और कुशाग्र का जल से अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अभिषेक के पश्चात सफेद चंदन या भस्म लगाया जाता है। उसके बाद सफेद फूल, बेलपत्र, बेल, भांग, धतूरा, बेर, शमी पत्र सहित अन्य से अभिषेक किया जाता है।

पीठाधीश्वर स्वामी रामाश्रम शास्त्री स्वामी महराज ने बताया कि भगवान शिव के पूजन से जहां सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है ऐसे में सभी सनातनधर्मियों को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्म और भगवान विष्णु भी भगवान शिव का पूजन करते हुए उनको महादेव कहते है।

देव के नाज़ुक पलों में गहराई लाने को लेकर अभिषेक शर्मा ने ज़ाहिर किए जज़्बात

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। ज़ी टीवी 'मर्द को दर्द नहीं होता' जैसी सोच को तोड़ते हुए ऐसे मजबूत किरदार सामने ला रहा है, जो अपनी कमजोरी दिखाने से नहीं डरते। समाज में अब भी यह गलत सोच है कि 'असली मर्द' वही होता है जो कभी टूटे नहीं, हमेशा संभला रहे और अपनी बातें दिल में ही दबाए रखे। लेकिन जब बात परिवार की आती है, तो कई पुरुष यह दिखाते हैं कि मजबूती के साथ-साथ नरमी भी हो सकती है। ज़ी टीवी के शो 'वसुधा' में देव का किरदार निभा रहे अभिषेक शर्मा ने दर्शकों के दिलों को छुआ है, सिर्फ उसकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उस खामोश-सी नर्मी के लिए भी, जो उसके सफर को खास बनाती है। एक आम टीवी हीरो से अलग, अभिषेक देव को कई रंगों वाला, अंदर से जुड़ा हुआ और बिल्कुल इंसानी किरदार मानते हैं। देव और वसुधा के सफर का अगला पड़ाव जानने के लिए देखिए 'वसुधा', रोज़ रात 9:30 बजे, सिर्फ ज़ी टीवी पर।

गंगा की रेती पर छवा द बंगला पर झूमे श्रोता, अवधी लोकनृत्य ने बांधा समां

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'चलो मन गंगा-यमुना तीर' कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत गुरुवार की सांस्कृतिक संध्या लोक रंग, संगीत और नृत्य की सुरमयी छटा से सराबोर रही। कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने संगम की रेती पर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या से आईं संगीता आहूजा एवं उनके साथी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत अवधी लोकनृत्य से हुआ, जिसने अपनी जीवंत भंगिमाओं और लोक-संवेदना से वातावरण को उल्लासमय बना दिया। इसके पश्चात शाम्भवी शुक्ला ने अपने सुमधुर गायन से समां बांध दिया। उन्होंने 'चलो मन गंगा यमुना तीर', 'गंगा की रेती पर छवा द बंगला', 'रंग डारूंगी मैं', 'जनि जा बरसाने होरी', 'सजा दो घर को गुलशन सा' तथा 'दमादम मस्त कलंदर' जैसी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया।

वाराणसी से आए अमृत मिश्रा एवं वंसुधरा ने कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति देकर अपनी लयकारी और भाव-भंगिमाओं से दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। इसके बाद मीरजापुर से पधारे शिवलाल गुप्ता ने लोकगीतों की मधुर प्रस्तुति देते हुए 'जय होवे जयकार हो', 'मैया मोरी जय जगदेव', 'हमरे मीरजापुर में मस्ती के चाल बा', 'महिमा न जानो गंगा महरानी' एवं 'फागुन मस्त महीना हो बलम' जैसे गीतों से वातावरण को भक्तिमय और लोक-रंग में रंग दिया।

कार्यक्रम का संचालन संजय पुरुषार्थी ने किया। इस अवसर पर केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा एवं लोकगायक उदय चंद्र परदेशी ने सभी कलाकारों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया।

बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन संगोष्ठी एवं विशाल भंडारे का होगा आयोजन

महामहोत्सव की विदाई पर प्रयागराज में होगा भव्य धार्मिक कार्यक्रम, जुटेंगे संत-महात्मा

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। माघ मेला महोत्सव विदाई समारोह के अवसर पर धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से ओत-प्रोत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सेक्टर-1 स्थित महावीर संगम अपार्टमेंट चौराहा पर सती अनसूया आश्रम, चित्रकूट धाम, प्रयागराज के तत्वावधान में संपन्न होगा।

इस पावन अवसर पर नागा संत शिरोमणि दामोदर दास जी महाराज के दिव्य सान्निध्य में अनुष्ठान, भंडारा, साधु सेवा एवं अतिथि सेवा का भव्य आयोजन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम 17 फरवरी 2026 को आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ सायं 4 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत समाज में व्याप्त बाल भिक्षावृत्ति की समस्या के उन्मूलन तथा बाल-बालिकाओं के शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास को लेकर बाल उन्नयन संगोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। यह संगोष्ठी दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें समाजसेवी, धर्मगुरु एवं बुद्धिजीवी वर्ग भाग लेंगे।

आयोजकों ने बताया कि इस संगोष्ठी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा भिक्षावृत्ति से मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया जाएगा।

कार्यक्रम को लेकर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दामोदर दास जी महाराज के शिष्य ओम दास जी, समाजसेवी मोनू गुप्ता, महावीर दास, दयाल दास, रविंद्र दास, देवेंद्र दास, वरिष्ठ पत्रकार राजेश सरकार, पत्रकार देवा श्रीवास्तव, सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। आयोजकों ने समस्त धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं, समाजसेवियों एवं क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पुनीत आयोजन में सहभागिता करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं।

कला से अनुभूति तकः 'विंसेंट-एर मृत्यु' ने मंच पर रचा संवेदनाओं का कैनवास

भारत रंग महोत्सव के दूसरे दिन कलाकारों ने जीता 'दर्शकों का दिल

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारत रंग महोत्सव के दूसरे दिन प्रेक्षागृह गुरुवार की संध्या मात्र एक रंगमंच नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसा 'फ्रेम' बन गया जहाँ कलाकार और दर्शक के बीच मानवीय संवेदनाओं का इतिहास रचा गया। भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत कासबा अर्घ्य, कोलकाता की नाट्य प्रस्तुति 'विंसेंट-एर मृत्यु' ने न केवल आँखों को नम किया, बल्कि मंच पर 'कंपोजिशन' और 'इमोशन्स' का एक ऐसा कोलाज प्रस्तुत किया, जो दुर्लभ है। प्रकाश की लकीरों में ढलती संवेदना को जब दर्शक मंच को देखता है, तो वह केवल पात्रों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे मौन को भी कैद करना चाहता है। कोलकाता की नाट्य संस्था कासबा अर्घ्य द्वारा प्रस्तुत नाटक 'विंसेंट-एर मृत्यु' ने विश्वप्रसिद्ध डच चित्रकार विंसेंट वान गॉग के जीवन को रंगमंचीय भाषा में अत्यंत प्रभावशाली ढंग से साकार किया। मनीष मित्रा द्वारा लिखित एवं निर्देशित इस प्रस्तुति ने वान गॉग के छोटे किंतु तीव्र और संघर्षशील जीवन की संवेदनात्मक यात्रा को एक जीवंत उत्सव के रूप में मंच पर उतारा, जिसकी परिणति वर्ष 1890 में उनकी मृत्यु के साथ होती है।

नाटक की संरचना में वान गॉग की प्रसिद्ध पेंटिंग्स के प्रोजेक्शन,

भाव-प्रधान संगीत और गैर-रेखीय कथन शैली का सशक्त संयोजन देखने को मिला। अतियथार्थवादी दृश्य संरचनाएँ, शारीरिक अभिनय और प्रकाश की सूक्ष्म रेखाओं ने कलाकार की आंतरिक मानसिक दुनिया को मूर्त रूप दिया। प्रस्तुति ने दर्शकों को एक इमर्सिव अनुभव प्रदान करते हुए यह अनुभव कराया कि कला केवल दृश्य नहीं, बल्कि अनुभूति का विस्तार है।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अजय कुमार मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज कमिश्नरेट, केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा, उपनिदेशक डॉ. मुकेश उपाध्याय एवं कार्यक्रम सलाहकार कल्पना सहाय द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर कलाप्रेमी, गणमान्य तथा एनएसडी के प्रतिनिधि प्रशासन उपस्थित रहे।

आज उद्योग की परिभाषा है निवेश, निर्यात और आर्थिक समृद्धि : 2017 से पहले प्रदेश में अपहरण, गुण्डा टैक्स और अपराध थी उद्योग की परिभाषा - नन्दी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 2026-27 के चौथे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने विधान सभा में विधायक डॉ. रागिनी सोनकर, विधायक डॉ. हृदय नारायण सिंह पटेल एवं विधायक समरपाल सिंह द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति के साथ ही रोजगार परक योजनाओं एवं प्रयासों से अवगत कराया। वहीं इस दौरान मंत्री नन्दी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश की औद्योगिक गति, दुर्दशा एवं गुण्डाराज पर तीखा हमला बोला।

मंत्री नन्दी ने कहा कि 2017 से पहले पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन उल्टा प्रदेश था, गुण्डा प्रदेश था। वहीं उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज उत्तर प्रदेश निवेश का प्रमुख गंतव्य बन कर उभरा है। मंत्री नन्दी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्य अगर धरातल पर रहते तो उन्हें धरातल की जानकारी होती। इनकी इंस्टाग्राम रील से शुरू होने वाली राजनीति फेसबुक तक पहुंच कर दम तोड़ देती है। पिछली सरकारों में अराजकता और अपराध के परिवेश में निवेश वेंटीलेटर पर था। समाजवादी पार्टी की सरकार में वन डिस्ट्रिक वन माफिया सिस्टम हावी था। वहीं आज वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट के साथ उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर है। सपा सरकार में उत्तर प्रदेश माफियाओं के लिए स्वर्ग था, वहीं आज डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स के लिए स्वर्ग है।

विधायक डॉ. रागिनी सोनकर द्वारा विधानसभा में तारांकित प्रश्न पिछले नौ वर्षों में औद्योगिक विभाग द्वारा धरातल पर कितने प्रतिशत औद्योगिक परियोजनाएं क्रियान्वित हो पाई हैं और प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है का जवाब देते हुए मंत्री नन्दी ने कहा कि 2018 से अब तक हुए चार ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से 12.10 लाख करोड़ रूपए की लागत से 16 हजार 478 औद्योगिक इकाईयों की ग्राउण्डिंग हुई है। जिसमें से अब तक 6 हजार 352 इकाईयों द्वारा अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भर कर दिया गया है। मंत्री नन्दी ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि 2016-17 के दौरान सकल राज्य घरेलु उत्पाद 13.30 लाख करोड़ था। वहीं वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद 30.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जिसके अनुसार जीएसडीपी में 127 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मंत्री नन्दी ने कहा कि 2017 के पहले कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता था। कोई उद्यमी यहां उद्योग लगाना नहीं चाहता था। अराजकता, भय और आशंका ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को पंचर कर रखा था। आज गाजियाबाद से

लेकर गोरखपुर तक और हमीरपुर से लेकर लखीमपुर तक प्रत्येक जनपद औद्योगिक विकास की रोशनी से जगमगा रहा है। 2017 से पहले प्रदेश में उद्योग की परिभाषा थी- अपहरण, गुण्डा टैक्स और अपराध। आज उद्योग की परिभाषा है निवेश, निर्यात और आर्थिक समृद्धि। प्रदेश में अब तक हुए ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से अब तक 38.55 प्रतिशत इकाईयों ने वाणिज्यिक उत्पादन धरातल पर प्रारम्भ कर दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 127 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है। इसक विस्तृत विवरण सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

मंत्री नन्दी ने सदन में विधायकों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी नीति, नियत और निर्णय तीनों स्पष्ट है। हमारा एक ही विजन है उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास, हमारा एक ही मिशन है उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि। मंत्री नन्दी ने कहा कि आजादी के बाद से 2016-2017 तक प्रदेश में 14 हजार 169 फैक्ट्रियां स्थापित थीं। वहीं 2024-25 तक प्रदेश में स्थापित फैक्ट्रियों की संख्या 27 हजार 351 पहुंच गई है। केवल आठ वर्ष में 13 हजार 182 फैक्ट्री स्थापित हुई है। मंत्री नन्दी ने कहा कि हमारी सरकार अब तक 16 हजार 592 करोड़ का इंसेंटिव उद्यमियों को दे चुकी है।

विधायक डॉ. हृदय नारायण सिंह पटेल ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि अब तक सम्पन्न हुए ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में कितनी कम्पनियों ने प्रतिभाग किया, कितने का इनवेस्टमेंट हुा और कितने को रोजगार मिला। इस प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री नन्दी ने अब तक सम्पन्न हुए ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का पूरा आंकड़ा रखते हुए बताया कि एक अप्रैल 2017 से तीन फरवरी 2026 तक फैक्ट्री एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार कुल 15 लाख 99 हजार 699 कर्मकारों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ।

विधायक समरपाल सिंह द्वारा निर्मित एवं प्रस्तावित एक्सप्रेस की संख्या के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री नन्दी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल पांच एक्सप्रेसवे संचालित हैं। एक एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। वहीं आठ एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। विगत तीन वर्षों में निर्मित एवं संचालित चार एक्सप्रेसवे के मेंटीनेंस में कुल 1000.72 करोड़ की धनराशि यूपीडा द्वारा व्यय की गई है।

अवैध इमारतों का जंगल,350 से ज्यादा अवैध इमारतों निर्माणाधीन जारी

प्रत्येक प्रभाग समितियों में दो से तीन बीट निरीक्षक की नियुक्ति, इसके बावजूद कार्रवाई शून्य

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगरपालिका क्षेत्र में अवैध निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। शहर में 350 से अधिक अवैध इमारतों के निर्माण की आशंका जताई जा रही है, जबकि कोर्ट से लेकर मनपा प्रशासन तक इस पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। इसके बावजूद अवैध बांधकाम रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मनपा अधिकारियों द्वारा विधानसभा सत्र में प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार वर्ष 2022 के बाद 291 अवैध निर्माण होने की पुष्टि की गई थी। इस आधिकारिक स्वीकारोक्ति के बाद भी शहर के विभिन्न हिस्सों में नए निर्माण तेजी से जारी हैं, जो नियोजन और नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते है।अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने और डीपीएल पूरा कर फाइलों को पूरा करने के लिए प्रशासक एवं आयुक्त ने प्रत्येक प्रभाग समिति में दो से तीन बीट निरीक्षकों की नियुक्ति की है। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं दे रहा। कई इलाकों में खुलेआम निर्माण कार्य जारी हैं।

प्रभाग समिति क्रमांक एक में तीन बीट निरीक्षक तैनात होने के बावजूद नागांव, पोगांग, गुलजार नगर, म्हाडा कॉलोनी, रामनगर, गायत्रीनगर और नुरीनगर जैसे क्षेत्रों में अवैध इमारतें निर्माणाधीन बताई जा रही हैं। वहीं प्रभाग समिति क्रमांक दो में दो बीट निरीक्षकों की मौजूदगी के बावजूद एक दर्जन से अधिक निर्माण कार्य बिना अनुमति के जारी होने की चर्चा है। सबसे अधिक निर्माण प्रभाग समिति क्रमांक तीन में होने की बात सामने आ रही है। यहां पद्मानगर स्थित मोनिका बार की गली में करीब आधा दर्जन अवैध इमारतें बन रही हैं, जिनमें कुछ बहुमंजिला और गगनचुंबी ढांचे शामिल हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस मार्ग से मनपा अधिकारियों का रोजाना आना-जाना होता है, लेकिन कार्रवाई न होने से सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ मामलों में कथित तौर पर रिश्वत के बदले फ्लैट लेने जैसी चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रभाग चार और पांच भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। नालापारा, दरगाह और आसपास के इलाकों में भी अवैध निर्माण जारी रहने की शिकायतें मिल रही हैं। शहर में तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण से सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और शहरी नियोजन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। नागरिक संगठनों और स्थानीय रहवासियों ने मनपा प्रशासन से पारदर्शी कार्रवाई और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

टेंपो से मिलावटी खाद्य पदार्थों का भंडाफोड़

पुलिस की कार्रवाई में 6 लाख का माल जब्त, अस्वच्छ जगह पर बन रहा था खतरनाक सामान

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। शांतिनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक टेंपो से बड़ी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की है, जो कथित तौर पर अस्वच्छ जगह पर तैयार कर बाजार में बेची जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 10 फरवरी को सलामतपुरा इलाके में खड़ी एक चारचाकी टेंपो (एमएच-01-ईएम-5938) में अवैध रूप से खाद्य पदार्थों का भंडारण किए जाने की जानकारी मिली थी। जांच के दौरान पता चला कि खाद्य सामग्री को अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार कर उसमें मिलावट की जा रही थी और बाद में उसे बाजार में बेचकर लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 6 लाख रुपये कीमत का टेंपो और संबंधित सामग्री जब्त की है। इस मामले में अब्दुल फैजल मोहिउद्दीन अंसारी (37) और विकास सुखदेव वानखेड़े (35) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस सुत्रों का कहना है कि आरोपियों द्वारा संगठित तरीके से खाद्य पदार्थों में मिलावट कर उन्हें बाजार में बेचने की आशंका है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। जांच में यह भी सामने आया है कि खाद्य सामग्री को अस्वच्छ स्थान पर संग्रहित किया गया था, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक कालु गवारी कर रहे है।

पास्को एक्ट में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कुमार प्रसाद के निर्देशन, व क्षेत्राधिकारी बांसी रोहिणी यादव के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार मौर्य थाना शिवनगर डिडई मय टीम द्वारा मु.अ.सं. 123/2025 धारा 351(3), 65(1) बीएनएस व पाक्सो एक्ट व 67 आई टी एक्ट से सबंधित वांछित अभियुक्त को स्वाद ढाबा डड़वा कोदई जोत से शिखर शुक्ला पुत्र स्व0 रामसुख शुक्ला साकिन बानकुईया को समय करीब 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया ।

नाबालिग से अश्लील हरकत का आरोप,युवक गिरफ्तार

निजामपुरा में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, पुलिस जांच जारी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी के निजामपुरा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ कथित अश्लील हरकत करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपनी नाबालिग बहन के संबंध में निजामपुरा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी रवि चंदनसिंह ठाकुर (19) को पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद उसने अनुचित व्यवहार किया, जिससे पीड़िता को मानसिक आघात पहुंचा।

एफआईआर के अनुसार, कथित घटनाएं अगस्त 2024 से लेकर हाल तक एक सोसाइटी में घटित होने का उल्लेख किया गया है। शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस ने प्राथमिक जांच कर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और 11 फरवरी 2026 को आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस सुत्रों ने बताया कि नाबालिग से जुड़े मामलों में कानून के तहत पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है, इसलिए मामले से संबंधित संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। पीड़िता की सुरक्षा और काउंसलिंग के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। मामले की माहिला पुलिस उप निरीक्षक चैताली जाधव कर रही है।

अज्ञात बाइक सवार ने युवक को मारी टक्कर, मौके से फरार

नदी नाका के पास हादसा, घायल को बिना मदद छोड़ भागा आरोपी

भिवंडी। भिवंडी के निजामपुरा क्षेत्र में हिट एंड रन की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। नदी नाका इलाके में तेज रफ्तार अज्ञात बाइक सवार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी और घायल अवस्था में उसे सड़क पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता चांद लियाकत शेख (35) 8 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे होटल में भोजन के लिए नदी नाका की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यातायात पुलिस चौकी के पास सड़क के बाईं ओर पैदल चलते समय पीछे से तेज गति में आए अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वह सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर तथा शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने घायल को सड़क किनारे से उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन आरोप है कि बाइक सवार बिना कोई मदद किए मौके से फरार हो गया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। निजामपुरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार बाइक सवार की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

टेलर ड्राइवर ने रास्ते में बेची लोहे की सरिया

सरिया माफिया फिर सक्रिय होने की आशंका

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी में ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़ा भरोसेघात और माल हेराफेरी का एक गंभीर मामला सामने आने के बाद परिवहन क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ट्रक के जरिए भेजी जा रही लोहे की सरिया को तय गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय रास्ते में ही उतारकर बेच देने का आरोप लगा है। नारपोली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसे आपराधिक साजिश तथा विश्वासघात के एंगल से देखा जा रहा है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन व्यवसाय से जुड़े शिकायतकर्ता धरमराज शिवशंकर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके ट्रक में लोड की गई लोहे की सरिया को चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में ही गायब कर दिया। शिकायत के मुताबिक, 11 फरवरी की सुबह करीब 5:30 बजे दापोडे रोड स्थित सरवाना होटल के पास ट्रक से माल उतारकर निजी लाभ के लिए बेच दिया गया। एफआईआर में बताया गया है कि ट्रक में मौजूद लोहे की सरिया के कई बंडल, जिनका वजन सैकड़ों किलो था, मौके पर गायब पाए गए। प्राथमिक जांच में करीब 30 हजार रुपये मूल्य के माल की हेराफेरी सामने आई है। पुलिस को यह भी आशंका है कि अन्य ट्रकों से जुड़े माल में भी इसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी जांच की जा रही है।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने भरोसे में लेकर माल अपने कब्जे में लिया और बाद में उसे बेचकर आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इस मामले में नारपोली पुलिस ने मोतीलाल मोहनलाल वर्मा सहित अरविंद कुमार धोले, विजय रामसुंदर बहादुर लोधी, मुकेश दिनेश प्रताप सरोज, अशरफ काजी, तौसिफ खान, रमाकांत तिवारी और असलम शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक धनराज केदार कर रहे है। पुलिस सुत्रों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है और जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। घटना के सामने आने के बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है और माल की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हेराफेरी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा।

डॉ जी एस तोमर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित

वाराणसी। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कायचिकित्सा विभाग में प्रायोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस काशी काय संगमम् में बीएचयू के माननीय कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डायरेक्टर डॉ एस एन शंखवार, ने आयुर्वेद संकाय के डीन प्रो पी के गोस्वामी एवं कायचिकित्सा के विभागाध्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद, डॉ के एन मूर्ति, डॉ जे एस त्रिपाठी एवं डॉ ओ पी सिंह की उपस्थिति में विश्व आयुर्वेद मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ जी एस तोमर को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया ।

रेलवे बोर्ड ने डानकुनि-सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को तेज़ी से पूरा करने के दिए निर्देश

भारतीय रेलवे ने केंद्रीय बजट 2026 में घोषित डानकुनि-सूरत डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को तेज़ी से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण परियोजना को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

गोरखपुर। यह नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग 2,100 किलोमीटर लंबा होगा। यह डानकुनि से सूरत तक पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुज़रेगा। इससे पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई तेज़ और आसान होगी। मालगाड़ियों का समय बचेगा और मौजूदा रेल मार्गों पर भीड़ कम होगी।

डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक के अनुसार बेहतर तकनीकी मानक तय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें उच्च क्षमता की बिजली व्यवस्था, बिना किसी लेवल क्रॉसिंग के ट्रैक और 'कवच' जैसी आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा बढ़े और अधिक माल ढुलाई हो सके।

इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को नए खर्च और नई समय-सीमा के अनुसार अपडेट किया जाएगा। इससे योजना और बजट बेहतर तरीके से तैयार किए जा सकेंगे और काम समय पर पूरा होगा। परियोजना को अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाएगा ताकि कई जगहों पर एक साथ काम शुरू किया जा सके। हर हिस्से के लिए अलग टीम बनाई जाएगी जो मौके पर रहकर काम की निगरानी करेगी। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि निर्माण शुरू होने से पहले की सभी तैयारियां तेज़ी से पूरी की जाएं। साथ ही, ठेके से जुड़े दस्तावेज़ भी पहले से तैयार किए जाएं ताकि काम शुरू करने में कोई देरी न हो।

इस परियोजना के लिए कितने कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, इसका आकलन भी किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड को हर हफ्ते प्रगति की जानकारी दी जाएगी, ताकि काम में किसी तरह की रुकावट न आए और परियोजना जल्दी पूरी हो सके।

मुंबई क्लाइमेट वीक : जलवायु कार्रवाई के लिए भारत का वैश्विक मंच

मुंबई में आयोजित होने वाला भारत का पहला क्लाइमेट वीक केवल चर्चा तक सीमित न रहकर वास्तविक जलवायु कार्रवाई की दिशा में एक मंच बनेगा। सरकार, उद्योग, विशेषज्ञ, युवा और नागरिकों को साथ लाकर यह पहल ग्लोबल साउथ के लिए जलवायु नेतृत्व का नया मॉडल प्रस्तुत करेगी।

खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी स्थिरता पर केंद्रित यह कार्यक्रम नवाचार, युवा सहभागिता और जनोन्मुख गतिविधियों के माध्यम से जलवायु कार्रवाई को आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। मुंबई से दिया जाने वाला संदेश स्पष्ट है जलवायु समाधान सामूहिक जिम्मेदारी और त्वरित कार्रवाई से ही संभव है। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की या केवल वैज्ञानिक चर्चा का विषय नहीं रहा। बाढ़, गर्मी की लहरें, अनियमित वर्षा और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ सीधे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। इस पृष्ठभूमि में 17-19 फरवरी 2026 को होने वाला मुंबई क्लाइमेट वीक भारत तथा विशेष रूप से ग्लोबल साउथ देशों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह केवल सम्मेलनों का आयोजन नहीं, बल्कि संवाद से कार्रवाई की दिशा में एक प्रयास है, जहां सरकार, उद्योग, विशेषज्ञ, युवा और आम नागरिक एक मंच पर आएँगे।

यह पहल प्रोजेक्ट मुंबई द्वारा महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एमएमआरडीए और बृहन्मुंबई महानगरपालिका के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य मुंबई को जलवायु समाधान की प्रयोगशाला बनाना है।

चर्चा से समाधान की ओर

इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावहारिक और लागू किए जा सकने वाले समाधान तलाशना है। मुख्य कार्यक्रम जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होंगे, जबकि शहरभर में कॉलेजों, सामुदायिक केंद्रों और सांस्कृतिक संस्थानों में गतिविधियां आयोजित होंगी।

नेतृत्व संवाद, विषयगत सत्र, एमसीडब्ल्यू इनोवेशन चैलेंज, युवा हरित नवाचार प्रतियोगिता और समाधान प्रदर्शनी इसका हिस्सा होंगी। 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल नीति चर्चा और जनभागीदारी को साथ लाता है, यह संदेश देता है कि जलवायु कार्रवाई सामूहिक जिम्मेदारी है।

पहले दिन अर्थशॉट प्राइज का विशेष सत्र होगा, जो प्रिंस विलियम की परिकल्पना पर आधारित है और प्रकृति, खाद्य प्रणाली तथा मानव-केंद्रित समाधान पर केंद्रित रहेगा। साथ ही रोड शो, कला व मीडिया कार्यक्रम और सस्टेनेबिलिटी मेला जलवायु कार्रवाई को रोजमर्रा के जीवन से जोड़ेगा।

'वार्तावरण' नामक नागरिक मंच लोगों को कविता, भाषण, कहानी और गीतों के माध्यम से जलवायु अनुभव साझा करने का अवसर देगा।

ग्लोबल साउथ की आवाज

विकासशील देश जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, परंतु निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। मुंबई क्लाइमेट वीक इस नेतृत्व को मजबूत करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रमुख भागीदार है, डेलॉइट रणनीतिक ज्ञान भागीदार है, जबकि टीआईएसएस और आईआईटी बॉम्बे शैक्षणिक सहयोगी हैं। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ इसमें शामिल हैं। यूनीसेफ का YuWaah युवा सहभागिता को मजबूत करेगा।

30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बिल गेट्स और हिलेरी क्लिंटन जैसी वैश्विक हस्तियों की उपस्थिति कार्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय महत्व देती है।

तीन प्रमुख स्तंभ

1.खाद्य प्रणाली – टिकाऊ कृषि और पोषण

2.ऊर्जा संक्रमण – स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव

3.शहरी लचीलापन – शहरों को जलवायु जोखिम से सुरक्षित बनाना

नवाचार और युवा नेतृत्व

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से नवाचार प्रतियोगिता आयोजित होगी। युवा हरित नवाचार कार्यक्रम भविष्य के जलवायु नेतृत्व को प्रोत्साहित करेगा।

विज्ञान, संस्कृति और नागरिक सहभागिता

व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं यह दर्शाएंगी कि जलवायु परिवर्तन सामाजिक मुद्दा भी है।

18 फरवरी को अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला छात्रों और वैश्विक नेतृत्व से संवाद करेंगे, विज्ञान और जलवायु जिम्मेदारी का संबंध स्पष्ट करेंगे।

जलवायु कार्रवाई का नया मॉडल

मुंबई क्लाइमेट वीक सार्वजनिक-निजी-नागरिक साझेदारी पर आधारित एक नया मॉडल प्रस्तुत करता है। यदि इससे ठोस साझेदारियां और नीति दिशा मिलती है, तो यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान की चुनौती है और यह मंच सामूहिक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भुसावल मंडल में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का सफल आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भुसावल मंडल में दिनांक 10 फरवरी से 12 फरवरी तक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों को राजभाषा नीति एवं उसके प्रभावी अनुपालन के संबंध में जागरूक करना था। कार्यक्रम के प्रारंभ में यूनुस अंसार मकानु, मंडल यांत्रिक इंजीनियर एवं संपर्क राजभाषा अधिकारी, भुसावल ने डॉ. विभावरी गोरे, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) मध्य रेलवे का स्वागत किया तथा उनके मार्गदर्शन हेतु आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में उपस्थित कर्मचारियों ने विषयवस्तु को अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायक बताया।

दिनांक 12 फरवरी 2026 को डॉ. विभावरी गोरे, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई द्वारा 'राजभाषा नीति' विषय पर विस्तृत एवं मार्गदर्शक व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इस व्याख्यान में डॉ. विभावरी गोरे, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) मध्य रेलवे ने संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक की महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के प्रमुख प्रावधानों को सरल एवं व्यावहारिक रूप में समझाया। अपने संबोधन में उन्होंने राजभाषा के प्रगति, प्रचार एवं प्रसार के लिए किए जाने वाले प्रयासों तथा कार्यालयों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। कर्मचारियों के राजभाषा संबंधी प्रश्नों का समाधान भी किया गया। कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्राप्त हुए, जिससे उन्हें कार्य निष्पादन में निश्चित रूप से लाभ होगा।

कप्तान दसुन शनाका की रिकॉर्ड तोड़ पारी, टी20 विश्व कप में श्रीलंका ने ओमान को बुरी तरह हराया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सह-मेजबान श्रीलंका ने पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 16वें मैच में ओमान पर 105 रनों की शानदार जीत दर्ज की। कप्तान दासुन शनाका के रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक और शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर टी20 विश्व कप 2026 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। कुसल मेंडिस (45 गेंदों में 61 रन), पवन रत्नायके (28 गेंदों में 60 रन) और दासुन शनाका (20 गेंदों में 50 रन) ने बल्ले से दबदबा बनाया, जबकि महेश थीक्षाना (4 ओवर में 2/11) और दुशमंथा चमीरा (20 ओवर में 2/19) ने गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया।

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद, श्रीलंका ने पावरप्ले के दौरान शुरुआती झटके झेले, जिसमें कामिल मिश्रा (8) और पथुम निस्संका (13) आउट हो गए। हालांकि, ओमान द्वारा उलटफेर करने की कोई भी उम्मीद कुसल मेंडिस और पवन रत्नायके के बीच महज 50 गेंदों में खेली गई 94 रनों की तूफानी साझेदारी के सामने जल्द ही खत्म हो गई। रत्नायके ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महज 28 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल था। 14वें ओवर में उनके आउट होने के बाद दासुन शनाका के आने से ओमान की टीम ने और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की।

शनाका ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 19 गेंदों में श्रीलंकाई बल्लेबाज द्वारा टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक बनाने का सबसे तेज रिकॉर्ड कायम किया। पांच छक्के और दो चौकों सहित उनकी नाबाद पारी ने श्रीलंका को 20 ओवरों में 225/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया - जो टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर और पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। 226 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की बल्लेबाजी शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा गई। दुशमंथा चमीरा ने पहले छह ओवरों में दो विकेट लेकर जतिंदर सिंह को एक रन पर और हम्माद मिर्जा को नौ रन पर आउट कर दिया।

अनुभवी मोहम्मद नदीम ने भले ही कुछ हद तक संघर्ष की उम्मीद जगाई हो, लेकिन चोटिल वानिंदु हसरंगा की अनुपस्थिति में श्रीलंका के स्पिन-प्रधान आक्रमण के सामने ओमान की टीम पूरी तरह से पस्त हो गई। नदीम की 56 गेंदों पर खेली गई 53 रनों की जुझारू पारी ने उन्हें टी20 विश्व कप इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का खिताब दिलाया, लेकिन यह ओमान के लिए काफी नहीं था।

अमेरिका मैच से पहले टीम इंडिया की अग्निपरीक्षा, अभिषेक-ईशान को लेकर टेंशन, नामीबिया के खिलाफ उतरेगी नई प्रारंभिक जोड़ी!

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप ए में नामीबिया के खिलाफ होने वाले मैच की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए एक संभावित संकट से जूझ रही है। हालांकि भारत ने अमेरिका के खिलाफ अपने पिछले मैच में जीत हासिल की, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था, जिससे टीम के सामने सवालों की झड़ी लग गई है। कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले को देखते हुए टीम प्रबंधन ने बिना किसी बाधा के तैयारी की उम्मीद की थी; लेकिन इसके विपरीत, उन्हें मेडिकल रूम में भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है।

सबसे बड़ी चिंता अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की विस्फोटक सलामी जोड़ी को लेकर है। शर्मा, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत की हालिया रणनीति की पहचान रही है, पेट की गंभीर समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि उन्हें बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन शारीरिक रूप से थकावट के कारण उनका जल्द वापसी करना मुश्किल लग रहा है। उनकी अनुपस्थिति में संजू सैमसन सलामी बल्लेबाजी के लिए प्रबल दावेदार हैं। हालांकि, चयन संबंधी मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब ईशान किशन नेट सेशन के दौरान चोटिल हो गए, जिससे रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है और सूर्यकुमार यादव या तिलक वर्मा को शीर्ष बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है।

ओपनिंग स्लॉट के अलावा, कई अन्य बदलावों की भी उम्मीद है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म को बरकरार रखना चाहता है। मुख्य कोच गौतम गंभीर के सामने विशेष रूप से चोट और बीमारी की समस्याओं को देखते हुए एक चुनौतीपूर्ण चुनौती है। अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में तेज बुखार के कारण बाहर रहने के बाद, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग इलेवन में वापसी की उम्मीद है। उन्हें टीम में शामिल करने के लिए, प्रबंधन को मोहम्मद सिराज के बारे में एक कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है, भले ही सिराज ने पिछले मैच में प्रभावशाली तीन विकेट लिए हों। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच में स्पिन गेंदबाजों को अक्सर मदद मिलती है, इसलिए कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने की मांग बढ़ रही है। अगर पिच सूखी हुई लगती है, तो वह किसी सीमर या यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती की जगह लेकर कलाई की स्पिन गेंदबाजी को एक नया आयाम दे सकते हैं। साइड स्ट्रेन से उबर चुके वाशिंगटन सुंदर अब उपलब्ध हैं। पावरप्ले में गेंदबाजी करने और निचले क्रम में बल्लेबाजी को मजबूती देने की उनकी क्षमता उन्हें रिंकू सिंह की जगह लेने का एक मजबूत दावेदार बनाती है, अगर टीम नामीबिया के मध्य क्रम के खिलाफ अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प चुनती है।

एचयूएल का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ दोगुना होकर 6,603 करोड़ रुपए

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। घरेलू उपयोग का रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर दोगुना होकर 6, 603 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एचयूएल ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अपने आइसक्रीम व्यवसाय को क्वालिटी वॉल्स (इंडिया) लिमिटेड को बेच दिया था जिससे उसके लाभ में यह वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने बताया कि नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से तिमाही के दौरान 576 करोड़ रुपए के असाधारण मद (हानि) दर्ज किए। कंपनी ने कहा, ''शुद्ध लाभ 6, 603 करोड़ रुपए रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 121 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से आइसक्रीम व्यवसाय को बेचने से उत्पन्न एकमुश्त सकारात्मक प्रभाव के कारण हुई..'' असाधारण मदों को छोड़कर शुद्ध लाभ एक प्रतिशत बढ़कर 2, 562 करोड़ रुपए रहा। वहीं असाधारण मदों और कर से पहले इसका लाभ 3, 495 करोड़ रुपए था। समीक्षाधीन तिमाही में उत्पादों की बिक्री से इसका राजस्व 5.71 प्रतिशत बढ़कर 16, 197 करोड़ रुपए हो गया। 2024-25 की इसी तिमाही में यह 15, 322 करोड़ रुपए था। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एचयूएल का कुल व्यय 6.37 प्रतिशत बढ़कर 13, 078 करोड़ रुपए रहा।

अन्य राजस्व सहित इसकी कुल आय 5.01 प्रतिशत बढ़कर 16, 580 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक प्रिया नायर ने कहा, ''इस तिमाही के दौरान, मांग के रुझानों में सुधार के शुरुआती संकेत दिखाई दिए जो सहायक नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित थे।'' उन्होंने कहा, ''हमने अपने ब्रांड के साथ व्यापक स्तर पर आकर्षण बढ़ाना जारी रखा, उच्च-वृद्धि मांग वाले क्षेत्रों में बाजार विकास को गति दी और त्वरित वाणिज्य के लिए एक समर्पित संगठन के साथ भविष्य के माध्यमों को विस्तारित करने की अपनी क्षमताओं को मजबूत किया।''

सुप्रीम कोर्ट की आरईआरए को कड़ी फटकार

कहा- ये अथॉरिटी सिर्फ बिल्डरों को फायदा पहुंचा रही है

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज (आरईआरए) के कामकाज पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस संस्था को समाप्त कर देना ही बेहतर होगा, क्योंकि यह घर खरीदारों की बजाय बिल्डरों को लाभ पहुंचाती प्रतीत होती है। कार्यवाही के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने आरईआरए की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए इसके कामकाज पर चिंता व्यक्त की।

सीजेआई ने टिप्पणी की कि यह संस्था बिल्डरों के हितों की सेवा करती हुई प्रतीत होती है। सीजेआई ने कहा कि यह डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को सुविधा प्रदान करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है और आगे कहा कि इस संस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देना ही बेहतर होगा। अदालत ने आगे कहा कि सभी राज्यों को अब उन लोगों के हितों पर विचार करना चाहिए जिनके लिए मूल रूप से आरईआरए संस्था का गठन किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आरईआरए कार्यालय को स्थानांतरित करने वाली अधिसूचना पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए स्टे पर भी टिप्पणी की। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसने पहले अधिसूचना पर रोक लगाई थी।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अदाणी समूह की एंट्री! 'अदाणी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड' का गठन

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अडानी पावर ने गुरुवार को न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी से मिलने वाली बिजली बनाने, भेजने और बांटने के लिए एक नई एटॉमिक एनर्जी यूनिट बनाने की घोषणा की। अदाणी पावर ने परमाणु एवं नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी 'अदाणी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड' (एएईएल) का गठन किया है।

नई यूनिट, जिसे ऑफिशियली अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, कंपनी की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी के तौर पर 5 लाख रुपये के शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ बनाई गई है। अडानी पावर शेयर प्राइसः अडानी पावर लिमिटेड के शेयर बुधवार को 1.75 रुपये (₹1.17इ) की बढ़ोतरी के बाद 150.85 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि एएईएल को 5, 00, 000 रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ गठित किया गया है। इसे 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 50, 000 शेयर में विभाजित किया गया है। अ दाणी पावर की एएईएल में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कंपनी ने कहा कि एएईएल का भारत में 11 फरवरी 2026 को गठन किया गया। उसी दिन इसे केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, कंपनी रजिस्ट्रार से निगमण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। इसमें कहा गया कि अदाणी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई है और इसलिए ही यह कंपनी की संबंधित पक्ष इकाई भी है।

यह भारतीय संसद द्वारा सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल पास करने के दो महीने बाद हुआ है, जिससे एक ऐसे सेक्टर में प्राइवेट हिस्सेदारी का रास्ता साफ़ हुआ है जिस पर अब तक सरकार का कड़ा कंट्रोल रहा है। इस कदम से भारत की न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया है।

नई सीपीआई सीरीज के तहत जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 2.75 प्रतिशत पर : सरकार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सरकार ने नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) सीरीज के तहत पहला महंगाई डेटा जारी कर दिया है। गुरुवार 12 फरवरी को घोषित डेटा के अनुसार, नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) सीरीज के तहत जनवरी 2026 में भारत की रिटेल महंगाई 2.75 प्रतिशत रही, जबकि उससे पिछले महीने में यह 1.33 प्रतिशत (पुरानी सीरीज के तहत) रही थी। यह डेटा एक दशक से ज्यादा समय में भारत की रिटेल महंगाई सीरीज में पहला बड़ा बदलाव है, जिसमें बेस ईयर 2012 से अपडेट करके 2024 किया गया है।

पिछले साल के आखिर में महंगाई बढ़ने लगी थी, जो पुरानी सीरीज के तहत एक महीने पहले के 0.71 फीसदी से दिसंबर में बढ़कर 1.33 फीसदी हो गई। अब नई सीरीज से पता चलता है कि महंगाई लगातार तीन महीनों से बढ़ रही हैं, क्योंकि इंडेक्स दिसंबर में 104.10 और नवंबर में 104.01 से बढ़कर जनवरी में 104.46 हो गया। बदले हुए सीपीआई इंडेक्स में एक बड़ा बदलाव यह है कि खाने की चीजों का वेटेज (हिस्सा) कम हो गया है। खाने की चीजों का वेटेज पहली बार 40 फीसदी से कम हो गया है। वहीं नॉन-फूड कैटेगरी अब इंडेक्स में 60 फीसदी से अधिक हैं, जो पहले लगभग 45 फीसदी था। साथ ही, ग्रामीण खपत को ज्यादा असरदार वजन दिया गया है, जो कुल मांग में इसके बढ़ते योगदान को दिखाता है। रिवाइज्ड यानी नई सीरीज के तहत फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 2.13 फीसदी हो गया। हालांकि कम वेटेज की वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन पर इसका कुल असर पिछली सीरीज के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है।

टी20 विश्व कप : आईसीसी की बड़ी पहल

कोलंबो में बीसीसीआई-बीसीबी के बीच खत्म होगी डेढ़ साल की तल्खी?

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच सुलह की पूरी तैयारी चल रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल भारत-पाकिस्तान मैच के लिए कोलंबो जा रहे हैं, जहां वे बीसीसीआई प्रतिनिधियों से बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पिछले डेढ़ साल से भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध नहीं बने हैं, क्योंकि 2025 में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति बिगड़ गई थी।

बांग्लादेश के अखबार 'प्रथम आलो' से बात करते हुए इस्लाम ने बताया कि इस हाई-प्रोफाइल मैच का निमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर से आया है। इस्लाम ने कहा कि आईसीसी ने फैसला कर लिया है। आईसीसी के प्रमुख हितधारक ये पांच एशियाई देश हैं और 15 तारीख को होने वाले भारत-पाकिस्तान विश्व कप मैच के लिए वे चाहते हैं कि इन पांचों एशियाई देशों के प्रतिनिधि एक साथ मैदान पर मौजूद रहें, मैच देखें और आपस में बातचीत करें।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान विश्व क्रिकेट संगठन में एशियाई गुट बनाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह बैठक बीसीसीआई के साथ तनाव को समाप्त करने का एक अवसर हो सकती है, तो इस्लाम ने कहा, 'आप इसे कुछ इसी तरह मान सकते हैं।' बीसीसीआई और बीसीबी के बीच दरार तब शुरू हुई जब भारतीय बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को उनके आईपीएल अनुबंध से मुक्त करने का निर्देश दिया, जिसका कारण उन्होंने कुछ अज्ञात परिस्थितियों का हवाला दिया।

ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि यह कदम बांग्लादेश में हुई राजनीतिक हिंसा से प्रेरित था, जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए विश्व कप मैचों के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया। हालांकि, बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी ने अपने आकलन के बाद इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि खतरे का स्तर कम से मध्यम है। विश्व निकाय के साथ लंबी बातचीत के बावजूद अपने रुख पर अड़े रहने के कारण बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया।

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 558 अंक लुढ़का, निफ्टी 25, 807 पर हुआ बंद

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। 12 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में कमजोरी का माहौल बना रहा और लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 400 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी फिसलकर 25, 850 के नीचे पहुंच गया। आईटी शेयरों में तेज बिकवाली और ग्लोबल बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। टेक महिंद्रा, इंफोसिस और विप्रो समेत कई आईटी शेयरों में 5इ तक की गिरावट देखी गई, वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर भी दबाव बना रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 558.72 अंक यानी 0.66इ गिरकर 83, 674.92 पर आ गया। वहीं निफ्टी 146.65 अंक या 0.57इ टूटकर 25, 807.20 के स्तर पर बंद हुआ।

गुरुवार को आईटी शेयरों में भारी दबाव रहा और निफ्टी आईटी इंडेक्स 4.5इ तक लुढ़क गया। बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी टेक, कोफोर्ज, एलटीआई माइंडट्री, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस और टाटा एलेक्सी जैसे शेयर 5-6इ तक टूटे। अमेरिकी बाजारों में आईटी शेयरों की कमजोरी, एआई से जुड़ी चिंताएं और ब्याज दरों में कटौती की कम संभावना ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ँद आधारित ऑटोमेशन भारतीय आईटी कंपनियों के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर असर डाल सकता है। एशियाई बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी बाजारों की गिरावट का असर भी घरेलू बाजार पर पड़ा। हैंगसेंग समेत कई एशियाई सूचकांक लाल निशान में कारोबार करते दिखे, जिससे भारतीय बाजार को सपोर्ट नहीं मिल पाया।

'30 की उम्र में करियर दोबारा शुरू करना डरावना था'

प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड छोड़ने के फैसले पर तोड़ी चुप्पी

मुंबई। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सबसे बड़ा चेहरा हैं, लेकिन सफलता के इस शिखर तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो जोखिम उठाया, वह किसी के लिए भी आसान नहीं था। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रियंका ने स्वीकार किया कि 30 की उम्र में अपने स्थापित बॉलीवुड करियर को 'दांव पर लगाना' और हॉलीवुड में शून्य से शुरुआत करना उनके लिए कितना खौफनाक था। प्रियंका ने हॉलीवुड में अपनी शुरुआत टीवी सीरीज क्वांटिको से की, जहाँ वह मुख्य भूमिका निभाने वाली पहली दक्षिण एशियाई अभिनेत्री बनीं। इसके बाद उन्होंने बेवॉच और द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। वैराइटी के साथ एक इंटरव्यू में, प्रियंका ने वेस्ट में अपने डेब्यू के बारे में बताया, '30 की उम्र में अपना करियर फिर से शुरू करना डरावना होता है। मैं सिक्योर थी।' उन्होंने आगे कहा, मैं फाइनेंशियली अच्छा कर रही थी। मैं जमी-जमाई थी। और मैंने इसे बर्बाद करने का फैसला किया। उन्होंने बताया, 'आज

मैं जहाँ हूँ, वहाँ पहुँचने में मुझे कई साल लग गए, बहुत मेहनत करनी पड़ी।' मैरी कॉम, बाजीराव मस्तानी और दिल धड़कने दो जैसी फ़िल्मों की सफलता के तुरंत बाद, वह 2015 के आसपास ऊए चली गईं, जब वह सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली भारतीय एक्ट्रेस में से एक थीं।

उन्होंने आगे कहा, 'मैं अब ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मैं वह चीज़ें चुन सकती हूँ जो मैं बनाना चाहती हूँ। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, और मैं इसे बहुत गंभीरता से लेती हूँ। हमारे बड़े होने में अनुशासन का बहुत बड़ा हिस्सा था। आपका शब्द ही आपका बंधन है। अगर आप कुछ कहते हैं, तो आपको उसके लिए खड़ा होना होगा।'

प्रियंका ने हॉलीवुड में आने पर अपने सामने आई स्टीरियोटाइप के बारे में बात की। 'लोग कमेंट करते थे, 'ओह, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, ' जैसे कि यह अनएक्सपेक्टेड हो। उन्होंने याद करते हुए कहा, 'हर बार जब मैं किसी मीटिंग में जाती थी, तो मेरे बारे में पहले से बनी एक सोच होती थी।' हालांकि, उन्होंने तय किया था कि वह इन सोच से टाइपकास्ट या सीमित नहीं रहेंगी। इसके बजाय, उनका मकसद 'बॉर्डरलेस एंटरटेनमेंट' का हिस्सा बनना था, जिसमें अलग-अलग देशों के एक्टर्स के साथ काम करना और कल्चरल बाउंड्रीज़ को पार करना शामिल था।

प्रियंका ने टीवी सीरीज़ क्वांटिको में लीड रोल के तौर पर हॉलीवुड में डेब्यू किया था। बाद में, उन्होंने बेवॉच और द मैट्रिक्स रिसरेक्शन्स जैसी बड़ी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए।

तमन्ना भाटिया बनीं ब्रांड एंबेसडर, 'गैर-कन्नड़' चेहरे को लेकर छिड़ी सियासी जंग

बैंगलुरू। कर्नाटक के प्रतिष्ठित और सदियों पुराने ब्रांड 'मैसूर सैंडल सोप' को लेकर राज्य में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को अपना नया ब्रांड एंबेसडर चुना है। मंगलवार को उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी भूमिका संभाल ली, लेकिन उनके 'गैर-कन्नड़' होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कई स्थानीय संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है।

विरोध करने वालों ने प्रसिद्ध साबुन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक गैर-कन्नड़ भाषी अभिनेत्री को चुने जाने पर सवाल उठाया है। सरकार ने अपने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि भाटिया का चयन योग्यता और व्यावसायिक विचार-विमर्श के आधार पर किया गया। राज्य के स्वामित्व वाली 'कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड' (केएसडीएल) द्वारा निर्मित उत्पादों की

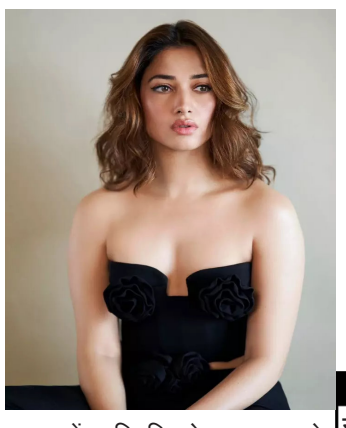

बाजार में उपस्थिति को मजबूत करने के प्रयासों के तहत भाटिया का कंपनी की ब्रांड एंबेसडर के रूप में दो साल का कार्यकाल मंगलवार से शुरू हो गया।

केएसडीएल एक ऐसा संगठन है जिसकी विरासत एक सदी से अधिक पुरानी है। भाटिया ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में संगठन के 57 उत्पादों का अनावरण किया, जिनमें 'मैसूर सैंडल सोप' भी शामिल है, जिसे अब एक नयी और आधुनिक पैकेजिंग में पेश किया गया है। जिन उत्पादों को नयी पैकेजिंग प्रदान की गई है उनमें चंदन का तेल, चमेली के सुगंध वाले साबुन, इत्र, टूथपेस्ट, नारियल तेल, पेट्रोलियम जेली और जैविक उत्पाद शामिल हैं।

इस अवसर पर भाटिया को दर्शाते कई विज्ञापन भी जारी किए गए। इसके अलावा संगठन की समृद्ध विरासत का वर्णन करने वाली दो 'कॉफी टेबल बुक' - सुगंधा सिरी और एरोमैटिक जर्नीज - का विमोचन किया गया। इस अवसर पर भाटिया ने कहा, ''मैसूर सैंडल सोप सिर्फ एक साबुन नहीं है। यह भावनाओं, बचपन की और पुरानी यादों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह शुद्धता और प्रामाणिकता का एक आदर्श मिश्रण है। यह साबुन लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है और इस संस्था के ब्रांड एंबेसडर के रूप में जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।''

सार्वजनिक सूचना

नायगांव स्टेशन पर यात्रियों के लिए फुट ओवर ब्रिज बंद किए जाने संबंधी सूचना

एमआरवीसी द्वारा नायगांव स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज तथा प्लेटफॉर्म के निर्माण/विस्तार का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के सिलसिले में नायगांव स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को प्लेटफॉर्म नंबर 2 एवं 3 से जोड़ने वाला मौजूदा उत्तर दिशा का फुट ओवर ब्रिज यात्रियों के लिए लगभग 1 एवं आधा माह की अवधि के लिए बंद किया जाना आवश्यक है। इस अवधि के दौरान यात्री एक 10 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज, दो 6.0 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज तथा एक 6 मीटर चौड़े सबवे का उपयोग कर सकते हैं। उपरोक्त के मद्देनज़र संबंधित फुट ओवर ब्रिज दिनांक 14.02.2026 से बंद रहेगा।

यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया जाता है।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
1118

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: x.com/WesternRly

राजिम कुंभ कल्प में सजा श्री पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार, राज्य अतिथि का मिला सम्मान

राजिम/रायपुर। छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ राजिम कुंभ कल्प में श्री पंडोखर सरकार जी का दिव्य दरबार 12, 13 और 14 फरवरी को विधिवत प्रारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति के बीच आयोजित इस दरबार में प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से भक्तजन पहुंच रहे हैं।

श्री पंडोखर सरकार आज प्रातः 9:00 बजे पंडोखर धाम से रायपुर स्थित आनंदम कचना पहुंचे, जहां अपने शिष्य टेकराम साहू के निवास पर उनका स्वागत किया गया। शिष्य मंडल के सदस्य राजीव अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर 1:00 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के निमंत्रण पर गुरुजी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। वहां लगभग दो घंटे तक सौहार्दपूर्ण चर्चा और भेंटवार्ता का कार्यक्रम चला।

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित इस भेंट के दौरान शिष्य मंडल के सदस्य राजीव अवस्थी, राकेश अग्रवाल, टेकराम साहू, फिजी ग्वालरे एवं विकास दुबे सहित अन्य शिष्यगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री निवास से प्रस्थान करने के पश्चात श्री पंडोखर सरकार राजिम कुंभ कल्प के लिए रवाना हुए, जहां सायं 4:00 बजे से दिव्य दरबार प्रारंभ हुआ और 6:30 बजे तक चला। दरबार में श्रद्धालुओं ने गुरुजी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

विशेष उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्री पंडोखर सरकार को 12, 13 और 14 फरवरी के लिए राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान किया गया है। इस निर्णय को भक्तों और आयोजकों ने प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बताया है।

राजिम कुंभ कल्प में आगामी दो दिनों तक चलने वाले इस दिव्य दरबार को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है।

आरपीएफ ने यूपी पुलिस को 3 विकेट से हराया, अखिल भारतीय पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश

नई दिल्लीः हरियाणा के करनाल स्थित मधुबन में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट (उत्तर क्षेत्र) में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है।

एक रोमांचक मुकाबले में, RPF ने उत्तर प्रदेश (UP) पुलिस को 3 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी बढ़त बनाई। टीम ने इससे पहले अपने 4 लीग मैचों में से 3 में जीत दर्ज की थी, जिससे उन्हें सेमीफाइनल (क्वालीफायर) के लिए आगे बढ़ने में मदद मिली।

आज के मैच में, RPF ने टॉस जीता और यूपी पुलिस के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए यूपी पुलिस ने 20 ओवर में 197 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया और एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। RPF ने इस लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए 19.5 ओवर में 197 रन बना लिए और एक करीबी व रोमांचक जीत हासिल की।

आरपीएफ के कप्तान डीआईजी (DIG) शशि कुमार ने दोनों टीमों के उत्कृष्ट खेल और खेल भावना की सराहना की। आरपीएफ के ए. वी. तोमर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' घोषित किया गया।

उत्तर क्षेत्र अखिल भारतीय पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का सफल आयोजन करनाल के मधुबन में हरियाणा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। RPF और दिल्ली पुलिस दोनों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जो दिल्ली में खेले जाएंगे।

मूसा गैंग से डरकर 1 महीने से गायब बीजेपी विधायक, अपनी ही पार्टी से हुए नाराज

बोले- किसी ने नहीं जाना हाल, एक कॉल तक नहीं किया

भोपाल **(एजेंसी)**। प्रदेश की सियासत में इन दिनों 'मूसा गैंग' की दस्तक और एक विधायक के लापता होने की खबर ने हलचल मचा दी है। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पिछले एक महीने से अंडरग्राउंड हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद से वे और उनका परिवार लगातार डर और चिंता में जी रहे हैं।

विधायक प्रदीप पटेल ने भावुक होते हुए कहा कि मूसा गैंग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही थी और क्षेत्र में उपद्रव कराने की साजिश रची जा रही थी। इसी भय के कारण उन्हें छिपने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी और सरकार उनकी अनदेखी कर रही है।

विधायक पटेल ने खुलकर कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी पार्टी के किसी बड़े नेता ने उनका हाल-चाल नहीं लिया। उन्होंने बताया कि घटना के दिन तक उनका फोन चालू था, लेकिन किसी ने संपर्क नहीं किया। उनका कहना है कि यदि फोन बंद भी होता, तो संगठन या प्रशासन अन्य माध्यमों से संपर्क कर सकता था।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी और सरकार दोनों इस मामले को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने

बताया कि संगठन लगातार विधायक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। खंडेलवाल ने कहा कि विधायक की सुरक्षा सुनिश्चित करना पार्टी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इसी बीच, मंगलवार 10 फरवरी की रात रीवा में 'मूसा' लिखी एक सफेद कार सड़कों पर घूमती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सतना नंबर की कार को जब्त कर लिया। जांच में सामने आया कि कार ड्राइवर का नाम अंतेश था। एएसपी रंजीव पाठक के मुताबिक, ड्राइवर ने दावा किया कि वह दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का प्रशंसक है, इसलिए उसने गाड़ी पर 'मूसा' लिखवाया था।

कांग्रेस के निशाने पर तीन मंत्री जीतू ने बर्खास्त करने की मांग की, सीएम को लिखा पत्र

भोपाल **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। जिसमें तीन मंत्रियों को हटाने की मांग की है। बजट सत्र से पहले उनकी इस मांग को लेकर प्रदेश की राजनीति में तूफान सा मच गया है।

जीतू पटवारी ने सीएम मोहन से प्रदेश के तीन मंत्रियों- मंत्री विजय शाह, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री राजेंद्र शुक्ला को हटाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा- आपकी सरकार के बजट सत्र में ऐसे मंत्री उपस्थित रहेंगे, जिनकी मंत्री मंडल में उपस्थिति अब उपयोगिता से उत्तर मांग रही है।

पटवारी ने मंत्री विजय शाह पर पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके मंत्रिमंडल में मौजूद मंत्री विजय शाह देश की बेटी और भारतीय सेना के अपमान के गंभीर आरोप हैं। जबकि छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से दर्जनों मासूम बच्चों की मौत हुई लेकिन स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला भी बजट सत्र में शामिल होंगे, इंदौर में दूषित पानी से कई लोगों की मौत हुई, कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि, यह शर्मनाक की ऐसे मंत्री अभी भी पद पर बने हुए हैं।

4 नहीं, 14 बच्चे पैदा करें हिंदू भाई

आईएमआईएम नेता शौकत अली के विवादित बोल, सरकार को दिया खुला चैलेंज

हैदराबाद **(एजेंसी)**। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बीते बुधवार देर शाम मुजफ्फरनगर में दो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए जनसंख्या के मुद्दे पर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। हिंदू संगठनों के 'चार बच्चे' वाले बयानों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए आबादी का बढ़ना जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के सवालों पर शौकत अली ने एक अनोखा तर्क दिया। हिंदू संगठनों के बयानों का जिक्र करते हुए शौकत अली ने कहा कि हिंदू भाइयों को 4 नहीं बल्कि 14 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चीन अपनी विशाल आबादी की वजह से ही आज दुनिया में इतना मजबूत है। भारत को भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने सरकार को चुनौती दी कि अगर जनसंख्या से इतनी ही परेशानी है, तो सरकार 'हम दो हमारे दो' का सख्त कानून क्यों नहीं लागू करती?

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से हो रहे निर्माण पर उठे विवाद पर भी शौकत अली ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान किसी को भी अपने धार्मिक स्थल का नाम चुनने की आजादी देता है। उन्होंने तंज

कसते हुए पूछा कि अगर कल को कोई अपने बेटे का नाम बाबर रख ले और काम शुरू करे, तो क्या सरकार उसे लाइसेंस नहीं देगी?

शौकत अली ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों को उनकी पहचान के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दाढ़ी, टोपी और गोश्त के नाम पर भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2022 के चुनाव में मिली हार को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि अब पार्टी जिला पंचायत और विधानसभा चुनावों के लिए जमीन पर संगठन को मजबूत कर रही है। सरकार के बजट को उन्होंने 'जनता के साथ धोखा' बताया और कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कोई राहत नहीं है।

'महाराज' के आते ही एक्टिव क्यों होते हैं?

पत्रकार के सवाल पर बुरी तरह झल्ला उठे मंत्री जी? बोले- निर्देश मत दो

भोपाल **(एजेंसी)**। ग्वालियर की सियासत में एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर आगमन के साथ ही प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की सक्रियता बढ़ जाती है? यह सवाल तब और सुर्खियों में आ गया जब मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री सिलावट एक पत्रकार के तीखे सवाल पर असहज नजर आए। बता दें कि तुलसी सिलावट प्रशासनिक अमले के साथ बीते दिनों ग्वालियर जिले में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसल के नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे। जहां उन्होंने किसानों को राहत राशि मुहैया कराने का ऐलान भी किया।

दरअसल, एक पत्रकार ने प्रभारी मंत्री से पूछा कि ग्वालियर में किसान परेशान हैं, सड़कों की हालत खराब है और विकास कार्य नगण्य दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि क्या उनका ग्वालियर दौरा केवल तब होता है जब 'महाराज' यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया शहर में आते हैं? इस सवाल ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। मंत्री के चेहरे के हाव-भाव से साफ झलक रहा था कि यह सवाल उन्हें नागवार गुजरा।

सवालों के जवाब में तुलसीराम सिलावट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साल भर का दौरा कार्यक्रम देख लिया जाए, तब स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने कितनी बार ग्वालियर का दौरा किया है। उन्होंने पत्रकार से कहा कि 'प्रभारी मंत्री को निर्देश मत दीजिए, समस्या बताइए, उसका समाधान किया

जाएगा।' साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका लेखा-जोखा उनकी पार्टी और सरकार रखती है, और ग्वालियर के हित में उठाए गए हर मुद्दे पर सरकार सजग है।

मंत्री के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा सकता है, वहीं सत्ता पक्ष इसे अनावश्यक विवाद बता रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है–क्या ग्वालियर में विकास कार्यों की रफ्तार संतोषजनक है? जनता को दौरे की संख्या से ज्यादा जमीन पर दिखने वाले कामों की अपेक्षा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बहस केवल बयानबाजी तक सीमित रहती है या ग्वालियर में विकास की गति पर भी इसका असर पड़ता है।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा एक्शन!

कम्फर्ट और स्लीप वेल अगरबत्ती पर लगा बैन, रिटेलर्स को दी कड़ी चेतावनी

मुम्बई **(एजेंसी)**। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में बिना मंजूरी वाले रसायनों से बनी मच्छर अगरबत्तियों के खिलाफ एक व्यापक प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध उत्पादों के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेष रूप से 'कंफर्ट' और 'स्लीप वेल' ब्रांड की अगरबत्तियों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि इनमें डाइमेफ्लुथ्रिन और मेपरफ्लुथ्रिन जैसे कीटनाशक रसायन पाए गए हैं, जो अगरबत्ती के रूप में उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं हैं।

महाराष्ट्र के कृषि निदेशक ने सभी विभागीय संयुक्त कृषि निदेशकों और कीटनाशक निरीक्षकों को ताजा सरकुलर जारी किया है। इसके तहत कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 के तहत तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को

छापेमारी करने, अवैध स्टॉक जब्त करने और दोषी निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने को कहा गया है।

सरकुलर में यह भी कहा गया है कि क्षेत्रीय अधिकारियों को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सीधे कृषि आयुक्तालय को सौंपनी होगी। इससे पूरे राज्य में एक समान और समयबद्ध प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस कार्रवाई की शुरुआत मुंबई में 'कंफर्ट' ब्रांड के खिलाफ की गई पिछली प्रवर्तन गतिविधियों के बाद हुई, और अब इसे पूरे महाराष्ट्र में विस्तारित किया गया है।

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में की गई जांच और प्रयोगशाला परीक्षणों से पुष्टि हुई है कि इन अगरबत्तियों में ऐसे रसायन पाए गए हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। जांच में यह भी सामने आया कि उत्पाद बिना किसी नियामक मंजूरी के बेचे जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं में सुरक्षा को लेकर भ्रम फैल रहा था। होम इंसेक्ट कंट्रोल एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। संगठन के मानद सचिव जयंत देशपांडे ने कहा कि अवैध और बिना मंजूरी वाले रसायनों का दुरुपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि यह प्रवर्तन उन लोगों के हित में है जो अनजाने में नकली मच्छर अगरबत्तियां खरीदते हैं।

अमेरिका की कड़ी चेतावनी

पेरू पर मंडरा रहा चीन का खतरा, सस्ते कर्ज़ की चुकानी पड़ सकती भारी कीमत

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चिंता जताई है कि चीन लातिन अमेरिकी देश पेरू के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर अपना नियंत्रण मजबूत करके उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी की यह चेतावनी पेरू की एक अदालत के उस फैसले के बाद आई है जिसमें एक स्थानीय नियामक ने चीन द्वारा बनाए गए विशाल बंदरगाह की निगरानी को सीमित कर दिया है। पेरू की राजधानी लीमा के उत्तर में चांकाय में स्थित 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से स्थापित गहरे पानी का बंदरगाह लातिन अमेरिका में चीन की पकड़ का प्रतीक बन गया है। यह बंदरगाह अमेरिका के साथ तनाव का केंद्र बिंदु भी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पश्चिमी गोलार्ध मामलों के ब्यूरो ने सोशल मीडिया मंच पर कहा कि वह "उन नवीनतम खबरों से चिंतित है कि पेरू अपने सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक, चांकाय पर नजर रखने में असहाय हो सकता है, जो लालची चीनी मालिकों के अधिकार क्षेत्र में है।" अमेरिका ने कहा, "हम पेरू के उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की देखरेख करने के संप्रभु अधिकार का समर्थन करते हैं। इसे इस क्षेत्र और दुनिया के लिए एक सबक के रूप में लें, सस्ते चीनी ऋण की कीमत संप्रभुता से चुकानी पड़ती है।"

भारतीय छात्रा की मौत पर सिएटल को चुकानी पड़ी भारी कीमत, परिवार से किया करोड़ों डॉलर का समझौता

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिका के सिएटल शहर ने 2023 में एक पुलिस अधिकारी की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर लगने से जान गंवाने वाली भारत की 23 वर्षीय स्नातकोत्तर छात्रा जाह्नवी कंदुला के परिवार के साथ 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर के समझौते पर सहमति जताई है। कंदुला को अधिकारी केविन डेव की गाड़ी ने उस समय टक्कर मारी थी, जब वह मादक पदार्थ संबंधी एक कॉल के बाद कार्रवाई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा वाले क्षेत्र में 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे। उनकी गाड़ी की आपातकालीन लाइट जल रही थीं और चौराहों पर सायरन का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। सिटी अटॉर्नी एरिका इवांस ने बुधवार को जारी बयान में कहा, 'जाह्नवी कंदुला की मौत हृदयविदारक है और शहर को उम्मीद है कि यह वित्तीय समझौता कंदुला परिवार को कुछ हद तक संतोष प्रदान करेगा।

जाह्नवी कंदुला का जीवन महत्वपूर्ण था। यह उनके परिवार, मित्रों और हमारे समुदाय के लिए मायने रखता था।' कंदुला सिएटल स्थित नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में सूचना प्रणाली (इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स) में मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही थीं। कंदुला के परिवार के वकीलों ने तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों पक्षों ने पिछले शुक्रवार को किंग काउंटी सुपीरियर कोर्ट में समझौते की सूचना दाखिल की। स्थानीय समाचार वेबसाइट 'पब्लिकॉला' ने सबसे पहले इस समझौते की खबर दी। कंदुला की मौत के बाद व्यापक प्रदर्शन हुए थे। लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर भड़क उठा जब एक अन्य अधिकारी के बॉडी कैमरा की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें वह हंसते हुए कंदुला के जीवन को 'मामूली' बताते और यह कहते सुनाई दिया कि शहर को 'सिर्फ एक चेक लिख देना' चाहिए। भारत के राजनयिकों ने भी मामले की जांच की मांग की थी।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)